RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

# माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com


**सुविचार**

सच को चाहे शक्कर में ही क्यों न डुबो दिया जाए, उसकी कड़वाहट कम नहीं होती।

सआदत हसन मंटो


वर्ष-06, अंक - 25 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 14 मार्च 2024 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए


## वल्लभ भवन में किस वजह से लगी आग और कौन दोषी...?

**भोपाल।** मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन में आग लगने के कारण का लगभग खुलासा हो गया है। जांच रिपोर्ट कमेटी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को सौंप दी है। रिपोर्ट में आगजनी का कारण शार्ट सर्किट बताया गया है तो वहीं इस हादसे के लिए कमेटी ने लोक निर्माण विभाग के फायर टेंडर व्यवस्था को जिम्मेदार माना है।

कमेटी ने रिपोर्ट में बताया कि, भवन में लूज वायरिंग, समय पर रखरखाव नहीं होने से ऐसी स्थिति बनी। घटना के बाद फायर टीम मौके पर पहुंच तो गई थी, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से आग भड़ गई। बता दें कि, नौ मार्च को मंत्रालय में लगी आग के कारणों का पता लगाने के लिए शासन ने एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस टीम को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तीन दिन में सौपना थी।

### 15 दिन में आएगी फाइनल रिपोर्ट

मंत्रालय में लगी आग के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट फॉरेंसिक साइंब लैब रिपोर्ट मिलने के बाद दी जाएगी। प्रमुख सचिव के अनुसार फाइनल रिपोर्ट 15 दिन में आएगी। इस सात सदस्यीय टीम में अध्यक्ष एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान हैं, जबकि सदस्य प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव लोक निर्माण डीपी आहूजा, एडीजी अग्निशमन सेवाएं आशुतोष राय, आयुक्त भोपाल पवन शर्मा और आयुक्त पुलिस हरिनारायणचारी मिश्रा शामिल हैं।

### तीसरी मंजिल पर लगी थी आग

गौरतलब है कि, नौ मार्च को वल्लभ भवन में आग लग गई थी। यह आग गेट नंबर पांच और छह के बीच बड़ी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर लगी थी। मंत्रालय में आग की सूचना नगर निगम फायर कंट्रोम रूम को सफाई कर्मचारी ने दी। इस आगजनी पर सेना, नगर निगम और एयरपोर्ट की दमकलों ने काबू पाया था।

## 2019 से 2024 के बीच खरीदे गए 22 हजार 217 चुनावी बॉन्ड

**नई दिल्ली, एजेंसी।** स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि, 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं।

एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के चंदे की जानकारी उपलब्ध करवा दी है। साथ ही चुनावी बॉन्ड को भुनाने की तारीख, चंदा प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम का विवरण भी चुनाव आयोग को उपलब्ध करवाया गया है।

### चुनावी चंदे का ब्योरा

- 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22 हजार 217 चुनावी बॉन्ड बिके, जिसमें से 22 हजार 30 कैश करवाए गए हैं।

- 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 18 हजार 871 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 20 हजार 421 को कैश करवाया गया।

- 1 अप्रैल 2019 और 11 अप्रैल 2019 के बीच कुल 3 हजार 346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और उनमें से एक हजार 609 को कैश करवाया गया।

एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, 14 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और कैश करवाए गए चुनावी बॉन्ड के संबंध में चुनाव आयोग को डेटा उपलब्ध कराया गया है। चुनावी बांड की खरीद की तारीख, खरीददारों के नाम और उनके मूल्यवर्ग का विवरण चुनाव आयोग को दिया गया है।

### सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लगाई थी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए चुनाव आयोग को 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था। चीफ जस्टिस ने एसबीआई से कहा था कि, 26 दिन में आपने क्या किया। ये बेहद गंभीर मामला है।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड से संबंधित मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की राशि का 13 मार्च तक खुलासा करने को कहा था। हालांकि, एसबीआई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने खारिज कर दिया।

## लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ के गढ़ में दरार

**भोपाल।** मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बड़ी दरार पड़ गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रदेश महासचिव चौधरी गंभीर सिंह भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ-साथ 40 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का हाथ थाम लिया। उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और न्यू जॉइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। चौधरी के साथ-साथ किसान कांग्रेस के अध्यक्ष चंद चौरिया, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सतीश मिश्रा, हर्रई जनपद अध्यक्ष कंचना उइके, चौरई नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका अर्जुन रघुवंशी, हर्रई जनपद पंचायत सदस्य रीति उइके, तामिया जनपद अध्यक्ष तुलसी परतेती भी भाजपा में शामिल हो गईं।

प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश शासन के मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, पार्टी के प्रदेश प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और मोनिका बट्टी उपस्थित थे। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. गोविंद सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से भोपाल में मुलाकात की। इसे लेकर गोविंद सिंह ने मीडिया से कहा कि, मैं यहां किसी भी चुनावी चर्चा के लिए नहीं आया था। जीतू पटवारी हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं। मैं पहले भी मिलने आता था, आज भी मिलने आया हूं। इस दौरान सिंह ने पार्टी से किसी भी तरह की नाराजगी से इंकार किया। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि, इस पर विचार कर रहे हैं।

वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गोविंद सिंह को द्रोणाचार्य कहा। उन्होंने कहा कि, गोविंद सिंह हमारे द्रोणाचार्य हैं। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी पार्टी से नाराजगी की बात कोरी अफवाह है।

## लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा वादा

**नई दिल्ली, एजेंसी।** कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक वीडियो जारी कर कहा, कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है, इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा तय करने जा रही है। 'नारी न्याय' गारंटी के अन्तर्गत कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं कर रही है। उन्होंने कहा कि 'महालक्ष्मी गारंटी' के तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी तथा 'आधी आबादी -पूरा हक़' के तहत केंद्र सरकार की नियुक्तियों में आधी हिस्सेदारी महिलाओं को मिलेगी। खरगे के अनुसार, 'शक्ति का सम्मान' के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन से संबंधित कर्मियों के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा तथा हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए 'अधिकार मैत्री' के रूप में एक क़ानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि, 'सावित्री बाई फुले छात्रावास' के तहत भारत सरकार देश भर में सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक छात्रावास बनाएगी और पूरे देश में इन छात्रावासों की संख्या दोगुनी की जाएगी। उन्होंने कहा, ''इसके पहले हमने 'भागीदारी न्याय', 'किसान न्याय' और 'युवा न्याय' घोषित किए हैं। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि हमारी गारंटी खोखले वादे और जुमले नहीं होते। हमारा कहा पत्थर की लकीर होती है। यही हमारा अब तक का रिकॉर्ड है, जब हमारे विरोधियों का जन्म हो रहा था तब से हम घोषणापत्र बना रहे हैं और उन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, नारी शक्ति को मेरा प्रणाम! कांग्रेस आपको 5 ऐसी गारंटी दे रही है जिनसे देश में महिलाओं का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा...कांग्रेस का लक्ष्य देश की आधी आबादी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और बराबरी का प्रतिनिधित्व देना है। उनका कहना था, ये 5 ऐतिहासिक कदम महिलाओं के लिए 'समृद्धि का द्वार' खोलने जा रहे हैं।

## वे हजारों करोड़ के घोटाले कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर में निवेश नहीं कर सके- पीएम मोदी

**नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, भारत की सेमीकंडक्टर हब बनने की महत्वाकांक्षा पांच दशक पहले पैदा हुई थी, लेकिन पिछली सरकारों ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र की उपेक्षा करते हुए आधुनिक तकनीक में निवेश करने के बजाय हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करने का विकल्प चुना। प्रधानमंत्री बुधवार को धोलेरा में 'इंडियाज टेकेडः चिप्स फॉर विकसित भारत' में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण का केंद्र बनाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए बुधवार को कहा कि, जब भारत वादा करता है, तो वह उसे पूरा भी करता है। मोदी ने तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी जिनमें दो गुजरात और एक असम में हैं। इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से लोगों को संबोधित किया। मोदी ने कहा, यह एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हम उज्ज्वल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं। 'मेड इन इंडिया' सेमीकंडक्टर चिप देश को आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की ओर ले जाएंगी।

देश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण का केंद्र बनाने के वादे पर मोदी ने कहा, जब भारत वादा करता होता है, तो भारत उसे पूरा करता है और लोकतंत्र भी उसे पूरा करता है। उन्होंने कहा कि, पिछली सरकारों ने हज़ारों करोड़ रुपए के घोटाले किए लेकिन वे सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए हजारों करोड़ का निवेश नहीं कर सकीं। इन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में गुजरात के धोलेरा में भारत का पहला 'फैब' संयंत्र और साणंद में 'आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट' केंद्र (ओएसएटी) शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने असम के मोरीगांव में 27 हजार करोड़ रुपए की लागत वाले 'आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट' (ओएसएटी) परियोजना का भी वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया। असम में जगीरोड में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि आज असम और पूर्वोत्तर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है।

## मुख्यमंत्री के बाद विधायक पद से भी दिया इस्तीफा

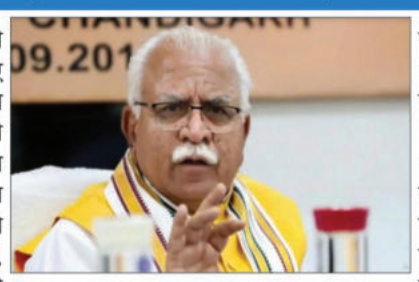

**चंडीगढ़।** हरियाणा में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके मनोहर लाल खट्टर ने अब विधायक पद भी छोड़ दिया है। वे हरियाणा की करनाल विधानसभा सीट से विधायक थे और उन्होंने बुधवार को इस पद से भी इस्तीफा दे दिया। इससे पहले, मंगलवार को अचानक घटे घटनाक्रम में मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। इसके बाद नायब सिंह सैनी को राज्य का नया सीएम बनाया गया है।

नायब सिंह सैनी अभी हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से सांसद हैं। उन्हें अगले छह महीने के भीतर किसी भी उपचुनाव के जरिए विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि, करनाल विधानसभा की जो सीट खाली हुई है, उससे वह चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। उधर, अटकलें हैं कि मनोहर लाल खट्टर आगामी लोकसभा चुनाव में करनाल सीट से भाजपा के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं।

हरियाणा में भाजपा और जेजेपी के बीच गठबंधन टूट गया है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बहुमत हासिल करने के उद्देश्य से बुधवार को फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया है। नए सीएम सैनी ने विधानसभा में कहा, मैं एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूं, मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है। मैं सिर्फ बीजेपी का एक पार्टी कार्यकर्ता हूं और आज मुझे इतना बड़ा अवसर दिया गया है। यह केवल एक पार्टी में ही संभव हो सकता है और वह भाजपा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ भी की। सीएम सैनी ने कहा, मैंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सब कुछ सीखा है। मैंने उनसे छोटी से छोटी चीजें भी सीखी हैं और उन्हें कैसे बनाए रखना है।

## ममता के घर में लग गई सियासी आग

**कोलकाता, एजेंसी।** टीएमसी सुप्रीमो ममता बेनर्जी के छोटे भाई बाबुन बेनर्जी ने बुधवार को पार्टी द्वारा पश्चिम बंगाल की हावड़ा लोकसभा सीट से प्रसून बेनर्जी को फिर से उम्मीदवार बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। हालाँकि, बाबुन बेनर्जी, जो इस समय नई दिल्ली में हैं, ने उन अटकलों से इनकार किया कि वह भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि, वह हावड़ा सीट से निर्दलीय के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, मैं हावड़ा लोकसभा सीट से उम्मीदवार के चयन से खुश नहीं हूं। प्रसून बेनर्जी सही विकल्प नहीं हैं। कई सक्षम उम्मीदवार थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। प्रसून ने मेरा जो अपमान किया, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। पूर्व फुटबॉलर, प्रसून बेनर्जी, हावड़ा सीट से टीएमसी के दो बार के लोकसभा सांसद हैं। ममता बनर्जी के छोटे भाई-बहनों में से एक बेनर्जी ने कहा कि, वह हावड़ा के पंजीकृत मतदाता हैं। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि दीदी (ममता बेनर्जी) मुझसे सहमत नहीं होंगी। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं हावड़ा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने कहा, हमें जो भी कहना है, हम जनता से कहेंगे। वे (भाजपा) कहते हैं कि हमें 400 सीटें मिलेंगी... हम सब कुछ जनता पर छोड़ देते हैं, जनता जिसे भी वोट देगी हम उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर भाजपा जबरदस्ती चुनाव कराएगी तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

## अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सीएए को लेकर चिंतित

**नई दिल्ली, एजेंसी।**

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ भारत में विपक्षियों पार्टियों की आलोचना के बीच, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने सीएए को ÷भेदभावपूर्ण÷ बताया है संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स से कहा है कि, सीएए ÷मूलभूत रूप से भेदभावपूर्ण है÷। उन्होंने कहा, जैसा कि हमने 2019 में भी कहा था, हमें चिंता है कि भारत का सीएए मूलभूत रूप से भेदभावपूर्ण है और भारत के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का उल्लंघन करता है। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि, उनका कार्यालय अभी यह मालूम करने की कोशिश कर रहा है कि सीएए के नियम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुकूल हैं या नहीं। साथ ही अमेरिकी सरकार ने भी इस कानून को लेकर चिंता जाहिर ही है। एनआरसी की वापसी का डर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने ईमेल पर रॉयटर्स को बताया, हम 11 मार्च की सीएए की अधिसूचना को लेकर चिंतित हैं। इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा हम इसकी करीब से निगरानी कर रहे हैं। प्रवक्ता ने यह भी कहा, धार्मिक स्वतंत्रता का आदर करना और कानून के तहत सभी समुदायों के साथ बराबरी से पेश आना मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं।

ऐक्टिविस्टों और मानवाधिकार वकीलों का कहना है कि, प्रस्तावित एनआरसी के साथ मिल कर यह कानून भारत के मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव कर सकता है। हालांकि भारत सरकार ने इस समय एनआरसी को लागू करने के बारे में कुछ नहीं कहा है। कुछ लोगों को यह चिंता है कि, सरकार कुछ सीमावर्ती राज्यों में बिना कागजात के रह रहे मुसलमानों की नागरिकता रद्द कर सकती है। कानून 2019 में ही पारित हो गया था लेकिन उस समय उसके खिलाफ देश के कई कोनों में इतने प्रदर्शन हुए कि सरकार ने उसे लागू नहीं किया। अब एक बार फिर इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं।

असम में विपक्षी पार्टियां और कई गैर सरकारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने पूरे प्रदेश में सीएए के खिलाफ सत्याग्रह करने की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मिजोरम में भी छात्रों का संगठन मीजो जीरलाई पॉल भी सीएए का विरोध कर रहा है। संगठन ने मंगलवार को कानून के नियमों की प्रतियां जलाईं। इस बीच सीएए पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इस तरह की कई याचिकाएं पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय सुप्रीम कोर्ट में ऐसी 230 से ज्यादा याचिकाएं लंबित हैं। ये याचिकाएं दिसंबर 2019 के बाद दायर की गई थीं। जनवरी 2020 में अदालत ने सीएए और एनपीआर पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था और कहा था कि अंत में पांच जजों की एक पीठ इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है।

## चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर क्या अटकेगा पेच, सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट

**नई दिल्ली, एजेंसी।** सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में केंद्र सरकार को नए कानून के तहत दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से रोकने की मांग की गई है। उच्चतम न्यायालय बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बनी समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली इस याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई करने पर सहमत हुआ है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने एनजीओ 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर किया और शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। भूषण ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए दलील पेश की थीं। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, मुझे अभी प्रधान न्यायाधीश से संदेश मिला है कि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए।

एनजीओ ने 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023' के एक प्रावधान की वैधता को चुनौती दी है। नए कानून के अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे और इसमें दो सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। हाल में निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के पद से इस्तीफे के बाद एनजीओ ने शीर्ष अदालत का रुख किया है।

निर्वाचन आयोग के दो नये निर्वाचन आयुक्तों के चयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक अब 14 मार्च को होगी। शीर्ष सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि कानून मंत्रालय ने 14 मार्च को दोपहर 12 बजे होने वाली बैठक के लिए समिति के सभी सदस्यों को एक संशोधित पत्र भेजा है। यह बैठक पहले 15 मार्च को शाम 6 बजे होनी थी।

निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय की पिछले महीने सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के शुक्रवार को अचानक इस्तीफे से निर्वाचन आयुक्तों के दो पद रिक्त हो गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति में एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

# सीएए: मुसलमानों को डरने की जरूरत नही

आखिरकार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चैंकाने वाला फैसला लेते हुए नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया। सीएए को लागू करना चैंकाने वाला नहीं था बल्कि ऐन रमज़ान पर लागू करने वाला चैंकाने वाला था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी के इस कदम के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये वही कानून है, जिसे लेकर कुछ साल पहले देश भर में कई प्रदर्शन हुए थे। दरअसल सीएए को लेकर या तो ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है या फिर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। ये कानून नागरिकता देने के लिए लाया गया है ना कि नागरिकता छीनने के लिए। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थी लोग सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। भारत में पांच साल से ज्यादा वक्त से रहने वाले लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जहां तक इसके विरोध या विवाद का प्रश्न है तो वो इसलिए हो रहा है कि क्योंकि सीएए के तहत मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं रखा गया है। सीएए का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में किसी एक समुदाय को छोड़ने वाला कानून नहीं लाया जाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोग भारत में शरण लेने के 11 साल बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2019 में जब सीएए संसद में पास किया गया था तब ये कहा जा रहा था कि सीएए के बाद सभी को कागज दिखाने होंगे। हालांकि, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में रहने वाले लोगों पर इस कानून का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। ये कानून सिर्फ उन लोगों के लिए है, जो दूसरे देशों से भारत आए हैं और नागरिकता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। भारत में रहने वाले लोगों को संविधान के तहत नागरिकता का अधिकार है। उत्तर पूर्व के ज्यादातर हिस्सों को सीएए से छूट दी गई है। असम के आदिवासी इलाके, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा संविधान की छठी अनुसूची के तहत आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड और मणिपुर को सीएए के प्रावधानों से छूट दी गई है।

11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम लागू होने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता बिना वैध पासपोर्ट और भारत के वीजा के बिना मिल सकती है। इन तीनों देशों के गैर-मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यक अपने माता-पिता, दादा-दादी या उनसे भी पीछे की पीढ़ी की राष्ट्रीयता के दस्तावेज दिखाकर भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। वीजा के बदले स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य की ओर से जारी सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। नागरिकता दिए जाने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान पासपोर्ट और भारत की ओर से जारी रिहाइशी परमिट के बजाय जन्म या शैक्षणिक संस्थानों के सर्टिफिकेट, लाइसेंस, सर्टिफिकेट, मकान होने या किराएदार होने के दस्तावेज पर्याप्त होंगे। वैध वीजा, एफआरआरओ यानी फॉरनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर से जारी रिहाइशी परमिट, जनगणना करने वालों की ओर से जारी पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भारत सरकार या अदालत की ओर से जारी कोई पत्र, भारत का जन्म प्रमाण पत्र, जमीन या किराएदार से जुड़े दस्तावेज, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, पैन कार्ड इश्योरेंस डॉक्यूमेंट, केंद्र, राज्य, बैंक या पीएसयू की ओर से जारी दस्तावेज, रेवन्यू ऑफिसर की ओर से जारी कागज, किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के चुने सदस्य की ओर से जारी दस्तावेज, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, बिजली, पानी बिल, ईपीएफ डॉक्यूमेंट, स्कूल सर्टिफिकेट, अकादमिक सर्टिफिकेट, म्युन्सिपेलिटी

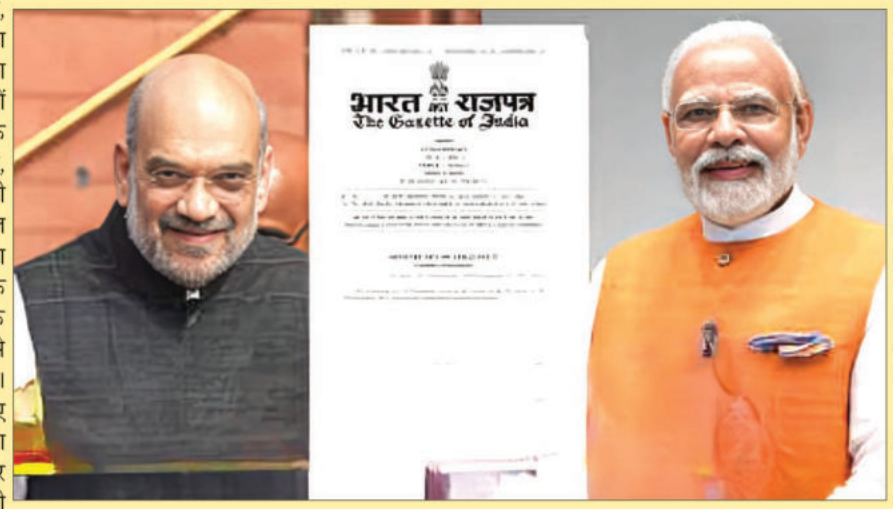


व्यापार लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट आदि को सबूत माना जाएगा। उन दस्तावेजों को भी मान्यता दी जाएगी, जिसमें माता-पिता या दादा-दादी के तीन में से एक देश के नागरिक होने की बात होगी। इन दस्तावेजों को स्वीकार किया जाएगा, फिर चाहे ये वैधता की अवधि को पार ही क्यों ना कर गई हो। इन दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करना होगा। सुरक्षा एजेंसी दस्तावेजों की जांच करेगी और फिर इसे आगे बढ़ाएगी। नए नियमों में इम्पावर्ड कमिटी और जिला स्तर पर केंद्र की ओर से ऐसी कमिटी बनाई जाएगी जो आवेदनों को लेगी और प्रक्रिया शुरू करेगी। इम्पावर्ड कमिटी का एक निदेशक होगा, डिप्टी सेक्रेटरी होंगे, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के स्टेट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर, राज्य के पोस्टमास्टर जनरल बतौर सदस्य होंगे। इस कमिटी में प्रधान सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और रेलवे अधिकारी होंगे। जिला स्तर की कमिटी के प्रमुख ज्यूरिसडिक्शनल सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट होंगे। इस कमिटी में जिले के इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर और केंद्र सरकार की ओर से एक नामित अधिकारी होगा। इसमें दो और लोगों को जगह दी जाएगी, जो तहसीलदार या जिलाधिकारी के स्तर का होंगे। सीएए के तहत पंजीकृत हर भारतीय को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

मोदी सरकार ने सीएए में ऐसे बदलाव किए हैं कि नागरिकता दिए जाने की प्रक्रिया में राज्य सरकारों की भूमिका ज्यादा ना हो। ये बदलाव इसलिए है कि राज्य सरकारों के इस कानून के विरोध करने से निपटा सकेगा। जब सीएए संसद में पास हुआ था तब भी कुछ और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसकी खिलाफत की थी। इस बार भी सबसे पहले ममता बनर्जी ने केन्द्र पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए का विरोध करते हुए कहा है कि आखिर रमजान के पहले ही इसे क्यों लागू किया गया है। उन?होंने कहा कि 2019 में असम में एनआरसी के नाम पर 19 लाख में से 13 लाख बंगाली हिंदू को लिस्ट से हटा दिया गया था, कई लोगों ने आत्महत्या की थी। मैं पूछती हूं, अगर वे लोग दर्खास्त करेंगे तो क्या उन्हें नागरिकता मिलेगी? उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा? उनकी संपत्ति का क्या होगा? जाहिर है पीएम मोदी को इसके विरोध का अंदेशा पहले से ही था। लिहाजा अब, मोदी सरकार ने ऐसे विरोध से निपटने के लिए कानून में बदलाव कर दिया है। वैसे तो इसे काफी पहले ही लागू हो जाना था लेकिन भाजपा सरकार ने मौके की नजाकत को भांपते हुए इसे लागू किया है। सीएए 11 दिसंबर 2019 को संसद से पास हुआ था और इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन इसके नियमों की अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इसे लागू कर दिया गया है। मालूम हो कि सीएए को लेकर देश भर में विरोध-प्रदर्शन हुआ था। केंद्र सरकार ने सीएए के बाद देश भर में एनआरसी लागू करने की बात कही थी। एनआरसी के तहत भारत के नागरिकों का वैध दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्रेशन होना था। सीएए के साथ एनआरसी को मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने के रूप में देखा गया था। आल इंडिया मुस्लिम जमात जो कि गैर सरकारी धार्मिक संगठन हैं, के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने सीएए के लागू होने पर कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। सीएए को लेकर पूर्व में हुए विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक लोगों ने गलतफहमियां पैदा की थीं। बहरहाल, सीएए के बाद एनआरसी की बारी है, देखिए आगे-आगे होता है क्या.....।

मुस्ताअली बोहरा

(अधिवक्ता एवं लेखक)

# जिला स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी एवं मिडिया सर्टिफिकेशन कमेटी का प्रशिक्षण संपन्न

**माही की गूंज, झाबुआ।**

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु 13 मार्च को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मिडिया सर्टिफिकेशन कमेटी एवं लोक सम्पति सुरक्षा दस्ता संबंधी प्रशिक्षण जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रदान किया गया।

जिले में पेड न्यूज, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मिडिया, सोशल मिडिया से संबंधित प्रकरणो का निराकरण करने एवं विज्ञापनो के प्रमाणिकरण के लिए मॉनीटरिंग कमेटी एवं मिडिया सर्टिफिकेशन कमेटी का प्रशिक्षण दिया गया।

लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल रूप से प्रभावशील हो जावेगी। इस दौरान विभिन्न व्यक्तियों, राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए या अन्य कार्य हेतु शासकीय, अशासकीय भवनों, दीवारों पर नारे लिखे जाने, बैनर लगाये जाने पोस्टर चिपकाए जाने, फ्लेक्स लगाये जाने तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंबो पर चुनाव प्रचार से संबंधित झण्डियाँ इत्यादि लगाये जाने के कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के अंतर्गत लोक सम्पति सुरक्षा दस्ता संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।

इस दौरान अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यनारायण दर्रो, मास्टर ट्रेनर्स हरीश कुमार कुण्डल, अजय कुशवाह, जिला सुचना विज्ञान अधिकारी कपिल कुमावत, तहसीलदार, थाना प्रभारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

# शादी का झांसा देकर चार वर्ष तक किया दुष्कर्म

**माही की गूंज, उज्जैन।**

एलएलबी कर रही छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित ने उसे शादी का झांसा देकर चार वर्ष तक शोषण किया। आरोपित की बहनों ने छात्रा के साथ अभद्रता कर मारपीट भी की।पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

महाकाल थाना पुलिस ने बताया कि, रामघाट मार्ग पर रहने वाली एलएलबी की छात्रा का परिचय आठ वर्ष पहले मयंक पिता रमेश निवासी रामघाट मार्ग से हुआ था। दोनों के बीच बातचीत होती रही और वर्ष 2020 में मयंक ने किसी बहाने से युवती को अपने घर बुलाया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद में मयंक ने कई बार युवती से दुष्कर्म किया और बाद में शादी करने से इंकार कर दिया। सोमवार को छात्रा अपनी बहन के साथ स्कूटी से जा रही थी तभी रास्ते में मयंक मिला और बात करने के बहाने उसे साथ लेकर गया। मौलाना मौजू की दरगाह के पास जाकर मयंक विवाद करने लगा। तभी आरोपित की बहन तारा यहां आ गई और गाली-गलौज करने लगी। दूसरी बहन नेहा व संतोष ने छात्रा के साथ मारपीट कर दी। छात्रा की शिकायत पर मयंक व उसकी बहनों के खिलाफ दुष्कर्म सहित मारपीट का केस दर्ज किया है। पुलिस ने मयंक को गिरफ्तार कर लिया है।

## विवाहिता से दुष्कर्म कर बनाया वीडियो

इधर ग्राम कलेसर थाना घट्टिया में रहने वाली 20 वर्षीय नवविवाहिता अपने पति के साथ एक वर्ष से गदापुलिया क्षेत्र में किराये के मकान में रह रही थी। उसके पति के काम पर जाने के बाद सोनू पिता रामदीन विश्वकर्मा निवासी राजस्थान ने महिला के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना लिया। सोनू ने महिला को धमकी दी कि किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर दूंगा। महिला ने पति को इसकी जानकारी दी और थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया।

# हाट बाजार में हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा

## बाइक दौड़ाने वालों को पहले समझाई दी फिर सख्ती की

**माही की गूंज, आम्बुआ।**

विगत दिनों से हाट बाजार में अधिक सवारियां बैठा कर तेज गति से बाइक बाजार में दौड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग सुरक्षा तथा शांति समिति में बार-बार मांग आ रही थी हाट बाजार में बाइकर्स तथा पैदल घूमने वाले युवाओं के झुंड द्वारा ग्रामीण युवतियों को परेशान किया जाता है। जिस पर उचित कार्रवाई की मांग की जा रही थी। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास के द्वारा भी हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश है। इसी तारतम्य में आम्बुआ में साप्ताहिक हाट बाजार (त्यौहारिया हाट) होने से बाजार में भीड़ अधिक रही, जिसमें युवा हुड़दंग कर रहे थे जिन्हें पहले तो समझ दी गई नहीं मानने पर सख्ती दिखाई गई। जिस कारण कई नागरिक उठाते रहे है। जिसके फल स्वरुप आम्बुआ हाट बाजार में पुलिस की शख्ती नजर आई जिसे देख कई ने रास्ता बदल लिया।

गूंज संवाददाता को आम्बुआ थाना प्रभारी योगेंद्र मंडलोई ने बताया कि, कस्बा निवासियों की बाइकर्स तथा युवाओं ने रास्ता बदलने में ही भलाई समझी। आगामी दिनों में भगोरिया तथा अन्य त्योहारों के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई जारी रहने की बात कही जा रही है ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

## आर्थिक राशि स्वीकृत

**माही की गूंज, झाबुआ।** 27 फरवरी को गुजरात राज्य में मजदूरी के लिए जा रहे जिनका चार पहियाँ वाहन से अहमदाबाद के समीप ढोलका में सड़क हादसे के दौरान पाँचों व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। जिसमे पांच में से चार मृतकों का घाटिया में पांचवें का पीपलीपाड़ा में अंतिम संस्कार हुआ। जिसमे मृतक दिलीपसिंह पिता नानसिंह बिलवाल, नितेश पिता नानसिंह बिलवाल, प्रमोद पिता भारतसिंह बिलवाल, राहुल पिता खुमसिंह बिलवाल, पायचंद पिता स्व. श्री वानिया भूरिया को मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा पात्र परिजनो दस-दस हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई।

## उपभोक्ता फोरम ने बिमा कम्पनी को शिकायत कर्ता को भुगतान करने का दिया आदेश

**माही की गूंज, झाबुआ।** परिवादी पीयुश पिता हिरालाल पटेल निवासी सिद्धेश्वर कॉलोनी, झाबुआ द्वारा विपक्षी स्टार हेल्थ एंड अलाईड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, से एक फैमेली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस लिया गया था। उक्त पॉलिसी के अंतर्गत परिवादी, उसके पुत्र दिवित पटेल एवं अन्य की जोखिम ग्रहण की गई थी एवं पॉलिसी 31 मार्च 2023 से 30 मार्च 2024 तक के लिए प्रभावी थी। माह अगस्त 2023 में परिवादी के पुत्र अवयस्क दिवित पटेल को डेंगू तेज बुखार आने के कारण गीतांजली चिल्ड्रन हॉस्पिटल एवं निओनेटल केयर, दाहोद गुजरात ले जाया गया। जहाँ डॉक्टर धनवी द्वारा परिवादी के पुत्र की जाँच करवायी गयी जिसमें डेंगू फीवर होना पाया गया एवं डॉक्टर के द्वारा परिवादी के पुत्र को हॉस्पिटल में 29 अगस्त 2023 से 02 नवम्बर 2023 तक भर्ती कर उपचार किया गया।

परिवादी ने अपने पुत्र के उपरोक्त हॉस्पिटल में भर्ती होने की सूचना बीमा कंपनी को दी थी। परिवादी के पुत्र को उक्त अवधि में उपचार में कुल राशि 26 हजार 974 रूपए खर्च हुए। परिवादी ने अपने पुत्र के उपचार में व्यय हुई राशि के मेडिकल दस्तावेज एवं हॉस्पिटल के असल बिल सहित बीमा कंपनी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया, जिस पर बीमा कंपनी ने दावा दर्ज किया। परिवादी के द्वारा दावा राशि की अदायगी हेतु बीमा कंपनी को कई बार कहा गया, परंतु विपक्षी बीमा कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। परिवादी के बीमा दावे को निरस्त कर दिया गया। इस तरह विपक्षी बीमा कंपनी ने परिवादी को बीमा दावे का भुगतान नहीं करके एवं बीमा दावे को उचित आधारों के बिना निरस्त कर दिया।

परिवादी विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से सेवा में कमी किये जाने के तथ्य को प्रमाणित करने में सफल रहा है, जिसके परिणामस्वरुप परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विपक्षी बीमा कंपनी के विरुद्ध स्वीकार कर आदेश पारित किया गया कि बीमा कंपनी परिवादी को उसके पुत्र के उपचार में व्यय की गई सम्पूर्ण राशि तथा ब्याज, मानसिक त्रास हेतु 3 हजार व परिवाद व्यय के 2 हजार के साथ राशि अदा करने का आदेश दिया।

# भगौरिया पर्व की तैयारियों को लेकर किया निरीक्षण

**माही की गूंज, झाबुआ।** राणापुर ब्लॉक के अंतर्गत लगने वाले भगौरिया पर्व की आवश्यक तैयारियों के संबंध में झाबुआ एसडीएम हरिशंकर विश्वकर्मा द्वारा बैठक में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए एवं भगौरिया स्थल राणापुर एवं कुंदनपुर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान तहसीलदार रानापुर सुखदेव डावर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

**कार्यालय रोगी कल्याण समिति पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र.)**

क्र./विज्ञप्ति/2024/534 पेटलावद, दिनांक13-03-2024

विज्ञप्ती

दिनांक 29/02/2024 को सिविल अस्पताल पेटलावद, जिला-झाबुआ में रोगी कल्याण समिति की साधारण सभा की बैठक रखी गई थी। जिसमें 12 बिन्दुओं पर चर्चा की गई थी। जिसमें सर्वसहमति से आवश्यक इलेक्ट्रिक उपकरण/एल्युमिनियम पार्टेशन का कार्य एवं अन्य कार्य करवाये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई थी। इस कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फार्म हेतु रूपये 1000/- का डी.डी./चेक सचिव रोगी कल्याण समिति पेटलावद के नाम से बनवाकर प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त कार्य हेतु प्रतिभुति राशि 10000/- रूपये का डी.डी./चेक फॉर्म के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। सभी आवेदक फॉर्म हेतु दिनांक 16/03/2024 से 20/03/2024 तक पुराना अस्पताल रोगी कल्याण समिति से प्राप्त कर सकते हैं एवं फॉर्म जमा करवाने की अंतिम तिथी 22/03/2024 सायं 04 बजे तक रहेगी।

नोट :- 1. निविदा सचिव रोगी कल्याण समिति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार रहेगा।

सचिव
रोगी कल्याण समिति
सामु.स्वा.केन्द्र पेटलावद

# अनीता चौहान के सामने कौन...?

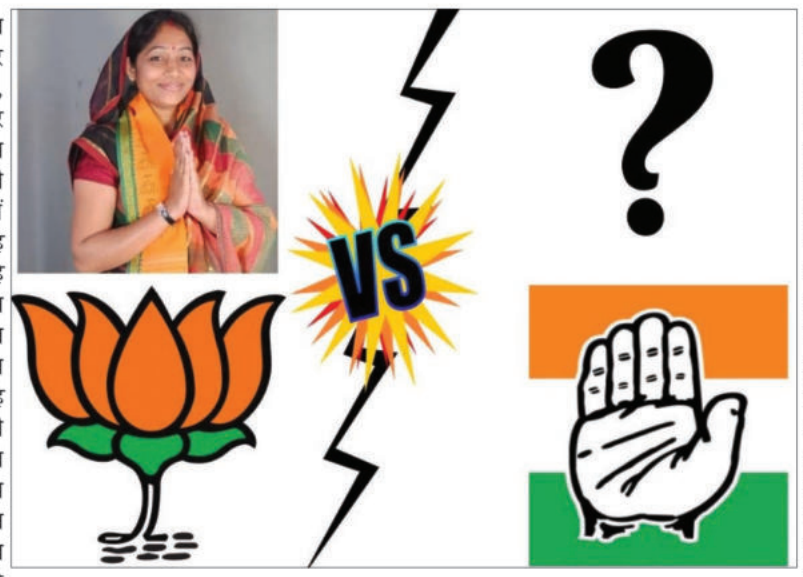


**माही की गूंज, झाबुआ।**

चुनावी शंखनाद होने में अब कुछ ही समय बचा है और दोनों ही प्रमुख दल अपने-अपने सेनापति (प्रत्याशी) चयन में लगे हैं। भाजपा जहां आक्रामक शैली अपनाए हुए हैं वही कांग्रेस अभी तक रक्षात्मक स्थिति में ही नजर आ रही है। फिलहाल कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती अपना घर सुरक्षित रखने की है। क्योंकि रोज कहीं न कहीं बड़ी संख्या में कांग्रेसी, भाजपाई हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। भाजपा ने अपनी पहली ही सूची में रतलाम लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी अनीता नागरसिंह चौहान को घोषित कर मानो वैज्ञानिक बडत ले ली है। वही कांग्रेस में कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया को टिकट के लिए संघर्षरत देखना क्षेत्र की जनता में अचरज पैदा कर रहा है। क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार होने वाले कांतिलाल भूरिया का नाम पहली सूची में आने की उम्मीद क्षेत्रवासी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की दो सूची के बाद भी रतलाम संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित न होना कांतिलाल भूरिया के कमजोर संपर्क की ओर इशारा कर रहा है। अभी तक कांग्रेस में कांतिलाल भूरिया निर्विवादित और सर्वमान्य नेता रहे हैं और सांसद, विधायक रहकर केंद्र और राज्य में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। ऐसे में क्षेत्रवासी यह मानकर चल रहे थे कि, भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान से ही कांग्रेस का मुकाबला होना तय है। लेकिन भाजपा द्वारा घोषित युवा चेहरे का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस भी कांतिलाल भूरिया के अलावा अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि, कांग्रेस अनुभव को प्राथमिकता देती है या युवाओं को आगे बढ़ती है...?

कांग्रेस अभी प्रत्याशी चयन में ही उलझ रही है, वहीं भाजपा प्रत्याशी ने अपना चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया है। अनिता नागरसिंह चौहान अपने पति वन मंत्री नागर सिंह चौहान के साथ संसदीय क्षेत्र के प्रमुख कस्बो का भ्रमण कर चुकी है। रतलाम और झाबुआ में चुनावी कार्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। वरिष्ठ नेताओं से संपर्क कर उन्हें चुनाव प्रचार हेतु राजी कर लिया गया है। ऐसे में देखना यह है कि, कांग्रेस अपने पत्ते कब खोले गी। भाजपा प्रत्याशी के लिए जहां रतलाम जिले का क्षेत्र नया है वही कांग्रेस यदि कांतिलाल भुरिया को प्रत्याशी घोषित करती है तो उनके सामने यह समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि वे पहले भी कई बार इस क्षेत्र के सांसद रहे हैं और पूरे क्षेत्र में वो जाना-पहचाना नाम है। वही अगर कांग्रेस यदि किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाती है तो उसे भी पूरे क्षेत्र में पहचान की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो कांग्रेस में दूसरा नाम सैलाना से पूर्व विधायक रहे हर्ष विजय गेहलोत का नाम भी चर्चा में है, इनके पिता स्वर्गीय प्रभु दयाल गहलोत भी इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं एक अन्य नाम जोबट विधायक सेना महेश पटेल का भी चल रहा है, हालांकि उनकी संभावना बहुत कम ही है।

### मोदी की ग्यारंटी बेअसर...

गत विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में एक बड़ी सभा की थी और डबल इंजन की सरकार और मोदी की ग्यारंटी के नाम पर विधानसभा चुनाव में वोट मांगे थे, लेकिन झाबुआ सहित जोबट, थांदला, सैलाना में मोदी की ग्यारंटी बेअसर रही थी। उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में मोदी एक बार फिर झाबुआ में सभा कर चुके हैं, हालांकि या चुनावी सभा नहीं थी, लेकिन यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने झाबुआ जिले से ही लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज किया था और पछले तीन चुनावो में अधिकतम मिले वोट में 370 वोट प्रत्येक बुथ पर बढ़ाने का लक्ष्य भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया था। अब देखना यह है कि, मोदी का या मंत्र इस लोकसभा में कितना कारगर साबित हो सकता है...? मोदी की ग्यारंटी कितने वोट दिला सकती है... संसदीय क्षेत्र के तीन मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना असर दिखा पाते हैं... यह तो लोकसभा चुनाव परिणाम ही तय करेगा।

# रामेश्वरम धाम पर हो रहे विशेष अनुष्ठान

**माही की गूंज, थांदला।**

काकनवानी पलवाड क्षेत्र के टाट वाले बाबा के नाम से जाने, जाने वाले रामदास त्यागी राम बाबा निसरपुर द्वारा रामेश्वर धाम, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम मणि तीर्थ पर परम पूज्य महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी की प्रेरणा से विश्व शांति व लोक कल्याण के लिए 15 दिवसीय 52 लाख महामृत्युंजय हवनात्मक अनुष्ठान किया जा रहा है।

यह मंदिर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के चारों ओर से घिरा हुआ है। रामेश्वरम मंदिर ज्योतिर्लिंग होने के साथ-साथ द्रविड़ शैली और अपनी शिल्प कला के कारण विश्व प्रसिद्ध है। मणि तीर्थ क्षेत्र रामेश्वर तीर्थ में कई प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। वागड़ राजस्थान के प्रखण्ड पंडित शास्त्री दिव्य भारती पंडिया बांसवाड़ा एवं शास्त्री रवि आचार्य थांदला जिला झाबुआ ने बताया कि, रामेश्वर तीर्थ में कई प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। हमारा लक्ष्य है हर वर्ष सभी 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर अनुष्ठान करना। इसी प्रकार से रामेश्वर तीर्थ में मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, वृंदावन, उत्तरप्रदेश के 108 विद्वान ब्राह्मण के द्वारा महान अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसमें सभी सहभागी बन सकते हैं। 108 विद्वान पंडितों द्वारा हवनात्मक महामृत्युंजय के 52 लाख जप एवं हवनात्मक अनुष्ठान जारी है। जो कि विश्व शांति के लिए यह अनुष्ठान किया जा रहा है। जिसकी पूर्ण आहुति दिनांक 24 मार्च को पूर्णिमा होली के दिन होना है। साथ ही श्री रामदास त्यागी टाट वाले बाबा द्वारा बताया गया कि, इस अनुष्ठान के साथ रामायण कथा का भी आयोजन किया जा रहा है जो की 15 मार्च से आरंभ होकर 24 मार्च को समापन होगा।

# सुंदरकांड के साथ थाने का हुआ नवीनीकरण

**माही की गूंज, काकनवानी।**

लंबे समय के बाद काकनवानी थाने का कायाकल्प बदला गया है। कई समय से थाने की मरम्मत की जाना बाकी थी जिसकी मरम्मत थाने पर नवीन पदस्थ आए थाना प्रभारी तारा मंडलोई ने पूरे थाने का प्लास्टर व रिपेयरिंग करवा कर कलर करवाया गया और थाने की बिल्डींग की उम्र बढ़ा दी। पूरा थाना चमचमाहट के बाद थाने में श्री सिद्धेश्वर रामायण मंडल के द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करवाया गया। सुंदरकांड शुरू करने से पूर्व पूजा के लिए पधारे जिले के नए कप्तान एसपी पदम विलोचन शुक्ला सह पत्नी रात्रि 8:00 बजे काकनवानी थाने पर आए और पूजा कर 20 मिनट में वापस लौट गए। इसके पश्चात सुंदरकांड पाठ शुरू किया गया और रात्रि 11:30 बजे थाना प्रभारी तारा मंडलोई द्वारा आरती पूजन कर प्रसादी वितरण की गई। इस मौके पर गांव के सैकड़ो गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे एवं थाना काकनवानी, चौकी हरी नगर, चौकी परवलिया एवं चौकी मदरानी के प्रभारी भी उपस्थित रहे।

# रमजान की हुई शुरूआत, छाई रौनक

**माही की गूंज, झाबुआ।**

रमजान महीने का चांद नजर आने के साथ मुस्लिम मोहल्लों में चहल-पहल बढ़ गई है। मंगलवार से पाक महीने का रोजा शुरू हो चुका है। पवित्र महीने रमजान का चांद 11 मार्च को दिखाई दिया था। मंगलवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने पहला रोजा रखते हुए रमजान की शुरूआत की है। अब यह क्रम लगातार एक माह तक चलता रहेगा। मुस्लिम समाज के लोग तीस दिनों तक रोजे रखकर खुदा से गुनाहों की माफी मांगते हैं। रमजान रहमतों की बारिश करने वाला महीना भी है। इस बार का रमजान गुलाबी ठंड में शुरू हो रहा है। इस बार करीब तेरह घंटे से अधिक समय का रोजा रहेगा। पंद्रह सालों बाद गुलाबी ठंड में तेरह घंटे के रोजे होने से रोजेदारों को थोड़ी आसानी होगी। शहर की मस्जिदें नमाजियों से गुलजार हो गई हैं।

मस्जिदों में सजावट के खास इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने भी मस्जिदों के पास और मुस्लिम इलाकों में साफ सफाई करा दी है। तरावीह की नमाज का लोगों में जबरदस्त जोश है। मुसलमान समुदाय मस्जिदों में जाकर तरावीह सुनते हैं। चांद नजर आने के साथ तरावीह की तैयारियों में लोग जुट गए थे। रमजान के चलते बाजार में खजूर, सूतफेनी, टोपी, सहरी और इफ्तार के सामान की खरीदी भी बढ़ गई है। रमजान में आमतौर पर हर घर में कुरआन की तिलावत की जाती है। रोजा खोलने के लिए खजूर को पसंद किया जाता है।

### इस्लाम के पांच मूलभूत सिद्धांतों में से एक है रोजा

इस्लामी जानकारी के अनुसार रोजा रखना इस्लाम के पांच मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। सभी मुसलमान को यह पांचों सिद्धांत का पालन करना काफी जरूरी है। इन पांच सिद्धांतों में नमाज, दान, आस्था, हज और रोजा शामिल है।

### इन लोगों को रोजा रखने से है माफी

इस्लाम में सभी बालिक लोगों को रोजा रखना अनिवार्य कहा गया है। हालांकि कुछ मामलों में रोजा रखने की छूट भी दी गई है अगर कोई बीमार है और वह दवा खाता है तो उसे रोजा रखने की छूट होती है। वहीं अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे भी रोजा रखने की छूट होती है। महिलाओं का अगर माहवारी का समय चल रहा है तो उन्हें भी रोजा रखने की छूट दी गई है। हालांकि पीरियड खत्म होने के बाद उन्हें बाकी सभी रोजे रखने होते हैं।

### रहमत, बरकत की शुरुआत

रोजदार को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खाने-पीने की मनाही होती है। इस्लामी कैलेंडर के बारह महीनों में रमजान को सबसे पाक और मुकद्दस महीना माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि रमजान के महीने में तीस रोजे रखकर अल्लाह की इबादत करने वालों का गुनाह माफ होता है। जिंदगी खत्म होने पर जन्नत में जगह मिलती है। रमजान के महीने में की गई इबादत का फल आम दिनों से सत्तर गुना ज्यादा हासिल होता है। इस महीने में अल्लाह अपने बंदों की इबादत से खुश होकर रहमतों की बारिश करते हैं। तीस दिन रोजे के बाद ईद की खुशियां मनाने का मौका मिलता है।

## श्रीमति रतन बाई बसेर का हुआ निधन

**माही की गूंज, सारंगी।** स्वर्गीय श्री शंभूलाल बसेर की धर्मपत्नी रतन बाई का स्वर्गवास शुक्रवार को हो गया, जिनका अंतिम संस्कार शनिवार को किया गया। रतन बाई काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रतन बाई स्वर्गीय श्री जयंतीलाल बसेर, पोपटलाल बसेर, स्वर्गीय अखिलेश बसेर, बाबूलाल बेसर की माताजी एवं जितेंद्र, अंतिम, कीर्तेश, आयूश, संयम बसेर की दादी थी। रतन बाई हमेशा धार्मिक आयोजन में भाग लेते रहे। अंतिम यात्रा उनके निज निवास से निकाली गई। यात्रा मुक्तिधाम पर पहुंची वहां पर उनके पुत्रों ने मंत्र उपचार के साथ मुखाग्नि देकर दाह संस्कार किया। अंतिम यात्रा में झाबुआ, गुजरात, राजस्थान के कलाल समाज तथा नगर के सभी समाज वर्ग, नगर के पत्रकार, आसपास ग्रामीण क्षेत्र के गणमान्य नागरिको ने अंतिम यात्रा में भाग लेकर श्रद्धांजलि दी।

# कुपोषण हारेगा झाबुआ जीतेगा: सामाजिक महासंघ कुपोषित बच्चों को लेगा गोद

**माही की गूंज, झाबुआ।**

सामाजिक महासंघ झाबुआ अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, धर्मजागरण, जन जागरूकता एवं खेल ओलंपिक जैसे प्रकल्पों को जन-जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहा है।

इसी कड़ी में कुपोषण हारेगा झाबुआ जीतेगा के मंत्र को साकार रूप प्रदान करते हुए सामाजिक महासंघ आगामी दिनों में 200 कुपोषित बच्चों को गोद लेकर न केवल उन्हें पोषण आहार प्रदान करेगा, बल्कि लगातार 3 माह तक उनके परिवार जनों के साथ संपर्क में रहकर उनका उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा।

इस आशय का निर्णय सामाजिक महासंघ की बैठक में 12 मार्च को लिया गया। साथ ही इस अवसर पर देश में नागरिक संशोधन कानून (सीएए) लागू किए जाने पर उपस्थित पूरे सदन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति धन्यवाद के साथ ही हर्ष व्यक्त करते हुए उनका तथा गृह मंत्री अमीत शाह का आभार व्यक्त किया।

उक्त जानकारी देते हुए सामाजिक महासंघ के अध्यक्ष नीरजसिंह राठौर एवं सचिव उमंग सक्सेना ने बताया कि, निक्षत अभियान के अंतर्गत लगभग 50 कुपोषित बच्चों को लगातार छः माह तक पोषण आहार प्रदान कर उन्हें पोषित करने का काम किया जा चुका है। जिले में बढ़ते कुपोषण के मामलों को देखते हुए सामाजिक महासंघ जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर 200 बच्चों को गोद लेकर उन्हें पूरी तरह से हृष्ट पुष्ट करने का बीड़ा उठाने जा रहा है।

बैठक के अवसर पर पद्मश्री रमेश परमार, आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय संयोजक ओम शर्मा, समाजसेवी यशवंत भंडारी ,रवींद्र सिसोदिया, श्रीमती भारती सोनी, विनोद जायसवाल, नवीन पाठक एवं भावना सेन ने अपने-अपने विचार व्यक्त करते हुए सामाजिक महासंघ के इस प्रयास की जमकर प्रशंसा की व साथ ही देश में लागू किए गए सीएए कानून के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार मानते हुए पोस्टर लहराकर उनका अभिवादन किया गया।

### कुपोषित बच्चों के लिए बनाई योजना

सामाजिक महासंघ के हरीश लाला शाह आम्रपाली एवं सुनील चैहान ने बताया कि, आगामी दिनों में जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर सामाजिक महासंघ 200 कुपोषित बच्चों को गोद लेगा। इसके लिए विशेष योजना तैयार कर ली गई है। इन बच्चों को लगातार पोषण आहार के रूप में भारत सरकार से मान्यता प्राप्त मोरविटा पाउडर दिया जाएगा। साथ ही इन बच्चों की सतत निगरानी रखने के लिए 20 सदस्यीय समिति भी बना ली गई है जो बच्चों के पालकों को रोजाना मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

### पड़ोसी देशों को सीएए जैसा कानून लागू करने की दी चुनौती

इस अवसर पर सामाजिक महासंघ द्वारा सीएए कानून लागू करने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए पोस्टर लहराकर उनका अभिवादन किया गया। सामाजिक महासंघ के अध्यक्ष नीरज सिंह राठौर ने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों को चुटीले अंदाज में चुनौती देते हुए कहा कि, यदि उनमें हिम्मत है तो वह भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर अपने-अपने देश में भी नागरिक संशोधन कानून लागू करके दिखाएं एवं हमारे यहां प्रताड़ित लोगों को उनके देश की नागरिकता प्रदान करें। इस बात पर सभी ने गर्म जोशी के साथ तालियो की गड़गड़ाहट करके इसका समर्थन एवं अनुमोदन किया। बैठक के अवसर पर डॉक्टर के के त्रिवेदी, पण्डित गणेश उपाध्याय, बिट्टू सिंगार, अजय सिंह पवार, पीडी रायपुरिया, कमलेश पटेल, भेरूसिंह सोलंकी, रूपसिंह खपेड, योगेंद्र सोनी, अरविंद व्यास, पुरुषोत्तम ताम्रकार, बबलू सकलेचा, नाना राठौर, राजू पाटीदार, शैलेंद्र चौरे, दीपक टेलर, नमिता कोठारी, आशीष चतुर्वेदी, मधुसूदन शर्मा, अखिल त्रिवेदी, शीतल जादौन, नीतू सिकरवार, भारती राठौर, वंदना व्यास, कल्पना सिसोदिया, सपना संघवी, देवकन्या सोनगरा, मीना टेलर, ममता सेन, नलिनी बैरागी, शशि त्रिवेदी, मुकेश बैरागी, सुनील शर्मा, किरण शर्मा, रंजीत राठौर, प्रिया त्रिवेदी, हार्दिक अरोड़ा, रविराज सिंह राठौर, नाथूलाल पाटीदार, रतनसिंह राठौर, कोमलसिंह कुशवाह सहित बड़ी संख्या में समाजसेवी उपस्थित थे कार्यक्रम का संचालन प्रदीप जैन ने किया व आभार कमलेश पटेल ने माना। अन्त में भारतमाता की जय घोष के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

## संपादकीय

# मनोहरलाल की मनोहर काहनी खत्म

सियासत में रणनीतियां जन कल्याण के लिये विरले ही बनती हैं। सत्ता हथियाने या सत्ता में बने रहने के लिए साम-दाम-दंड-भेद सहित तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाना आम बात है। महाभारत से लेकर अब तक यही सिलसिला जारी है। पाण्डवों को पांच गांव से भी वंचित रखे जाने पर कुरुक्षेत्र में यही कुछ हुआ। अब इसे संयोग ही कहा जा सकता है कि हरियाणा में चुनावी महाभारत के लिये एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अंततः कुरुक्षेत्र को ही पहल दी है। मनोहर लाल मंत्रिमंडल की मनोहर कहानी खत्म कर मंगलवार सायं कुरुक्षेत्र से ही पार्टी सांसद नायब सैनी को हरियाणा सरकार की कमान सौंपी गई। हालांकि वह विधायक भी नहीं हैं, फिर भी सियासत की चौसर पर फेंके उनके मोहरे पर ही पार्टी हाईकमान ने अपनी मुहर लगाई। प्रदेश के सत्ता पटल पर चौबीस घंटे के भीतर हुए इस नाटकीय घटनाक्रम का लब्बोलुआब यह है कि मंच के अभिनेता मनोहर लाल भले पार्श्व में चले गये हों, मगर पलायन में वह कतई नहीं गये। मंच पर होने वाले नायाब अभिनय के निर्देशक मनोहर लाल ही होंगे इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं होना चाहिए।

यह तो स्वाभाविक है कि लगातार दो पारियों में एक ही चेहरे के नेतृत्व से जनता का मोहभंग होने की आशंका अक्सर बनी रहती है। गुणा-जोड़ के गणित में और सियासी विज्ञान में महारत रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नये मुखौटे से बदलाव करके गुजरात मॉडल का सफल प्रयोग यहां भी दोहराया है। मंगलवार की सायं हुए इस बदलाव के संकेत दरअसल मोदी ने सोमवार सुबह ही गुरुग्राम में द्वारका हाई-वे के उद?घाटन भाषण दे दिए थे। मोदी ने हरियाणा में पार्टी प्रभारी रहते हुए मनोहर लाल से अपने घनिष्ठ संबंधों की एक तरह से याद ताजा कराई थी। उन्होंने स्मरण किया कि, दरियों से लेकर मोटरसाइकिल तक पर वे इकट?ठे बैठते रहे हैं। यह बात भी जग जाहिर है कि जहां मनोहर लाल अतीत काल में मोदी के सारथी रहे, वहीं उन्हीं दिनों में नायब सैनी एक सामान्य कार्यकर्ता या यूं कहे एक टाइपिस्ट के रूप में मोदी और मनोहर के सारथी थे। अतः सोमवार सुबह मोदी द्वारा व्यक्त किये गये उद?गारों की पुष्टि मंगलवार शाम ढलते-ढलते 'विदाई भावनाओं' के रूप में हो गई।

सोशल मीडिया या सियासत के कुछ गलियारों में चल रही इस चर्चा से हम इत्तेफाक नहीं रखते कि जन मन भर जाने की वजह से मनोहर लाल अतीत में भेज दिए गए हैं। मनोहर लाल पर मोदी के विश्वास की पुष्टि करीब छह माह पूर्व भी हुई जब प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद पर बदलाव करके जाट नेता ओम प्रकाश धनखड़ की जगह उनके पसंदीदा उम्मीदवार नायब सैनी के नाम पर ही मुहर लगी थी। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने की पटकथा भी जमा-गुणा और जातिगत गणित के अंतर्गत मनोहर-मोदी की सियासी स्याही से लिखी गई। गठबंधन भंग करने के मुख्यतः दो कारण रहे। एक, पार्टी में गठबंधन को लेकर आंतरिक रोष और दूसरे पार्टी में यह मंथन भी चल रहा था कि, जजपा की संगत में जाट वोट मिलने की संभावना न के बराबर थीं। इसलिये सत्ता के आवंटन में देवीलाल के प्रति जन भावनाओं का आदर बराबर रखा गया है। दुष्यंत भले निपटा दिए गए हों, लेकिन देवीलाल के सुपुत्र निर्दलीय विधायक चौ. रणजीत सिंह को मंत्री के रूप में बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही गैर जाट व अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के चेहरे के रूप में नायब सैनी का पत्ता खेला गया। वर्ष 2014 से जीटी रोड के हलकों पर केंद्रित गैर जाट कार्ड के बलबूते सत्ता पर काबिज भाजपा ने अब सियासत की चौसर पर कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जजपा के दुष्यंत चौटाला और इनेलो के अभय सिंह चौटाला के बीच जाट वोटों का बंटवारा करने का खेल खेलते हुए गैर जाटों का पासा अपने पक्ष में फेंकने का कूटनीतिक प्रयास किया है। आज की सियासत है भी सत्ता तक सीमित, जन कल्याण की बातें तो गौण होकर ही रह जाती हैं।

# चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए सार्थक पहल

चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था जब से हुई थी, उसके औचित्य पर सवालिया निशान लग रहे थे। शंका इस बॉन्ड को लेकर नहीं, इसके बारे में जनता को जानकारी न देने को लेकर थी। यह तो देश के मतदाता को बताया जा रहा था कि कितने के बॉन्ड बिके और किस पार्टी के हिस्से में कितने रुपये आये, पर यह बताने से लगातार इंकार किया जाता रहा कि पैसा दिया किसने। यह जानकारी यदि मतदाता को मिल जाती तो शायद उसे यह भी समझ आ जाता कि बॉन्ड खरीदने वाले ने किसको क्या दिया और उसके बदले में उसे क्या मिला? यही बात थी जिसे छिपाया जा रहा था। लेकिन क्यों? क्यों मतदाता को यह पता न चले कि किस धन्नासेठ ने किस राजनीतिक दल को कितना दिया है? एक तरफ तो हमने जानकारी के अधिकार को जनतांत्रिक मूल्य के रूप में स्वीकारा है, और दूसरी ओर राजनीतिक दलों और कार्पोरेट के आर्थिक रिश्तों पर इस तरह पर्दा डालने की कोशिश का क्या मतलब निकाला जाये?

मतलब साफ है। इस व्यवस्था के चलते राजनीतिक दल, विशेषकर सत्तारूढ़ दल के लिए अपने आर्थिक व्यवहार की अनियमितता को छिपाना आसान हो रहा था। जनतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई लड़ने वाले इस 'आसानी' का विरोध कर रहे थे। मामला अदालत में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मतदाता को यह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है कि किसने किस राजनीतिक दल को कितना पैसा दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड जारी करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक निश्चित तिथि तक यह सारी जानकारी देने का निर्देश भी दिया था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उस तिथि के एक दिन पहले स्टेट बैंक ने न्यायालय को यह बताया कि जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उसे अधिक समय की आवश्यकता है। उसने 'अधिक समय' को भी परिभाषित कियाद्ध बैंक ने जानकारी देने के लिए उतना समय मांगा था, जितने में देश में आम चुनाव हो जाते। मतलब साफ था- बैंक चाहता था कि उक्त जानकारी चुनाव के बाद दी जाये ताकि सत्तारूढ़ दल को होने वाला संभावित खतरा टल जाये। यह निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि जानकारी किसी दल विशेष के लिए ही खतरा उत्पन्न करती, पर यह अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि यह खतरा सत्तारूढ़ दल के लिए अधिक होता। इसीलिए स्टेट बैंक की इस पेशकश को सत्तारूढ़ दल के बचाव की एक कोशिश समझा गया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी उपलब्ध न कराने के लिए स्टेट बैंक बहानेबाजी ही कर रहा था। उच्चतम न्यायालय ने इस बहानेबाजी को समझा और स्पष्ट शब्दों में बैंक को निर्देश दिया कि एक दिन में ही सारी जानकारी चुनाव-आयोग को उपलब्ध कराये और चुनाव-आयोग को भी निर्देश दे दिये गये कि वह भी एक निश्चित दिन तक यह जानकारी देश के मतदाता तक पहुंचा दे। बैंक ने शीर्ष अदालत के निर्देश पर आयोग को जरूरी जानकारी उपलब्ध करा दी है।

न्यायालय की इस कार्रवाई और निर्णय को जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की कोशिश के रूप में समझा जा रहा है, हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो यह मानते है कि उच्चतम न्यायालय अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे हस्तक्षेप की आवश्यकता भी थी और प्रतीक्षा भी।

चुनावी बॉन्ड के बारे में बरती जा रही गोपनीयता ही सवालों के घेरे में नहीं थी, कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चंदे की सीमा का समाप्त किया जाना भी संदेह उत्पन्न करने वाला था। पुरानी व्यवस्था के अनुसार कंपनियां अपने लाभ का सात प्रतिशत ही चुनावी चंदे के रूप में दे सकती थीं, यह सीमा हटाने का मतलब था कंपनियों को यह अवसर देना कि वे सम्बन्धित राजनीतिक दल को मनचाहा पैसा दे सकें। इसे रिश्वत के रूप में समझा जाना स्वाभाविक हो। शायद यही सब देखते हुए न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में बरती जाने वाली गोपनीयता को अनावश्यक और अजनतांत्रिक माना। अब यह समझा जा सकता है कि जनता को यह पता चल सकेगा कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया और संभव है यह भी पता चल जाये कि इस चंदे के बदले में कोई अनुचित काम तो नहीं हुआ।

बहरहाल, उम्मीद की जानी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने में मददगार सिद्ध होगा। लेकिन, इस संदर्भ में जो कुछ हुआ है, उससे यह सवाल तो उठता ही है कि स्वायत्त सरकारी एजेंसियां सरकार के दबाव में तो काम नहीं कर रहीं? आखिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी देने के लिए इतना अधिक समय क्यों मांगा? क्या कोई दबाव था उस पर? आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई जैसी शक्तिशाली एजेंसियों पर सरकारी दबाव में काम करने के आरोप लगते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बैंकों पर सरकारें दबाव नहीं डालती रहीं, पर चुनावी बॉन्ड के मामले में स्टेट बैंक जैसी समर्थ संस्था पर सरकारी दबाव का ऐसा आरोप लगना जागरूक नागरिकों के लिए अतिरिक्त चिंता का विषय होना चाहिए। चुनावी बॉन्ड को लेकर बरती गयी अनावश्यक गोपनीयता के बाद बैंक पर सत्तारूढ़ दल के कथित दबाव का संदेह होना एक गंभीर बात है। जैसा कि कहते हैं, न्याय होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए, स्वायत्त संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अधिकारों-कर्तव्यों के प्रति सजग होंगी। अतिरिक्त समय की मांग करके, और चुनावों के समय के साथ अवधि के जुड़ने से उत्पन्न संदेह न होता तो बेहतर था।

विश्वनाथ सचदेव

यहीं, चुनाव-आयोग के गठन का मसला भी कम महत्वपूर्ण नहीं। पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता विपक्ष मिलकर आयोग के सदस्यों का चुनाव करते थे, लेकिन अब संसद में बहुमत का सहारा लेकर सरकार ने नया कानून बनाया है, मुख्य न्यायाधीश चयन-समिति में नहीं रहे, उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा किसी मंत्री को उसमें शामिल किया गया है। यह स्थिति भी संदेह और भ्रम उत्पन्न करने वाली है। चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश का न होना समिति को कमज़ोर ही बनाता है। अब जो स्थिति है उसमें प्रधानमंत्री को मनमानी करने का अवसर मिल जाता है। इस तरह के मामले में ऐसी मनमानी को उचित तो नहीं ही कहा जा सकता। जो अनुचित है, उसका समर्थन भी कैसे हो?

जनतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी रक्षा होनी ही चाहिए। तभी इस व्यवस्था में भरोसा बनेगा, बढ़ेगा। सत्तारूढ़ पक्ष का दायित्व इसमें बड़ा है; पर विपक्ष और मतदाता की जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है।

# अब तो झूठ का धंधा हो गई पॉलिटिक्स

टीवी चैनलों की आफत है रोज नये बवाल कहां से लायें। और बवाल खुद ब खुद चल कर आ जायें, तो उन्हे लंबे वक्त तक टिकाकर रखना बहुत मुश्किल काम है। यूक्रेन युद्ध को चले दो साल हो लिये। अब सिर्फ एकाध चैनल है जो यूक्रेन की कवरेज दिखाता है। यूक्रेन के युद्ध से पब्लिक बोर होने लगी कि गाजापट्टी का युद्ध आ गया। युद्ध खौफनाक होता है, सबके लिए नहीं। हथियार बेचने वाले और टीवी चैनलों पर टीआरपी बेचने वालों की फुल मौज का वक्त ही होता है युद्ध।

यूक्रेन के बाद गाजापट्टी युद्ध को भी अब करीब छह महीने होने वाले हैं। आतंकी संगठन हमास मान नहीं रहा है, इस्राइल तो बिलकुल नहीं मान रहा है। हमास का हाल उस कुत्ते जैसा हो गया है, जिसने अपनी ताकत की गलतफहमी के चलते शेर की पूंछ मरोड़ दी। अब कुत्ते को ही मरोड़ा जा रहा है। अब इस्राइल नहीं छोड़ रहा, कह रहा है कि अब हमास को पूरा ही मरोड़ देंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मारकाट करने से पहले अपनी असली ताकत आंक लेनी चाहिए।

पिटाई का एडवांस्ड संस्करण है-तुड़ाई, अब हमास की तुड़ाई हो रही है और कोई भी नहीं बचा पा रहा है। कोई नहीं बचाता है दरअसल, सबको अपने हित बचाने होते हैं। बचने की तैयारी पहले करके ही झगड़ा करना अक्लमंदी होती है। आतंकी संगठन और आतंकी देश इस तरह की अक्लमंदी रखते तो वो आतंकी क्यों होते। अब हमास के साथ एक ऐसा देश है, जो खुद आतंकी भी है और

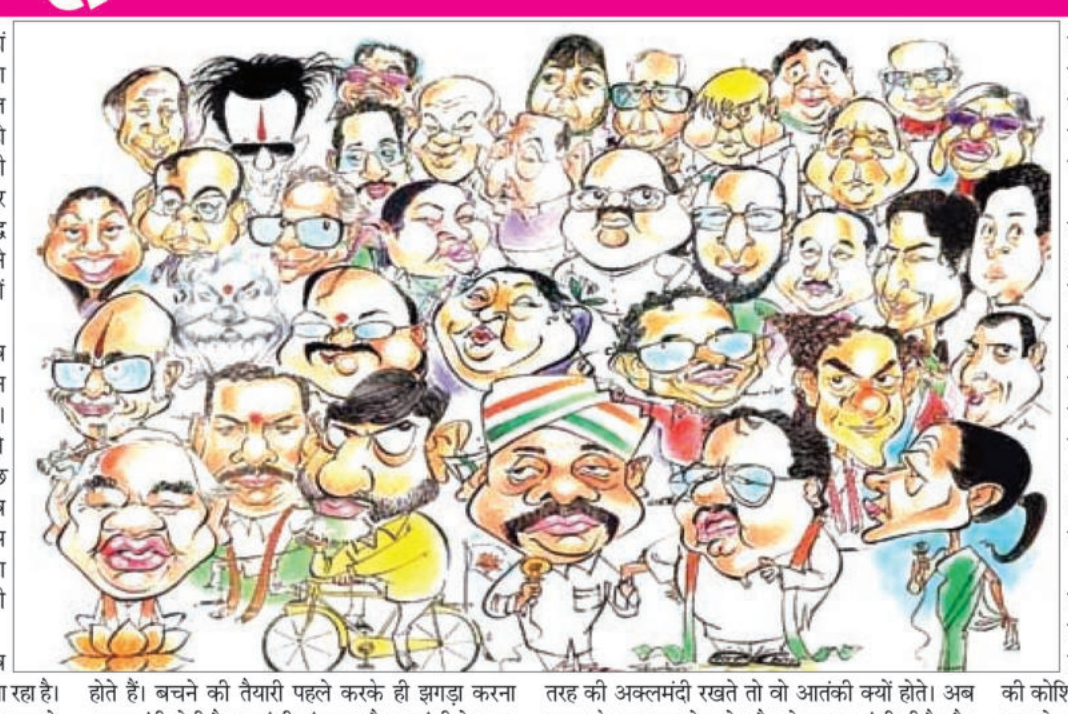

भिखारी-पाकिस्तान हमास के साथ है। पर पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है। वक्त किसी का भी भौकाल, असर कम कर देता है। एक वक्त था जब आंध्रप्रदेश के नेता चंद्रबाबू नायडू भाजपा के खिलाफ बोलते थे और खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। अब भाजपा के करीब हैं। पुरानी बातों को भूलना बहुत जरूरी है, वरना बंदा पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। जिसको कल कोसा है, उसे आज अपना खास बताना होता है। पॉलिटिक्स का धंधा बहुत डेंजरस है। कुल मिलाकर पॉलिटिक्स झूठ का धंधा हो लिया है।

आलोक पुराणिक

अब नीतीश कुमार ने कह दिया है कि वह वापस लौटकर नहीं जायेंगे, यह बात अगर तीन बार और बोल दें, तो समझिये कि वापस जाने वाले हैं। कोई बंदा अगर बहुत ज्यादा सच बोलने की कोशिश करता दिखे, तो समझ लेना चाहिए कि कतई झूठ बोल रहा है।

# उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रहे है किसान

कई दशक पहले, प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी एवं वैज्ञानिक डॉ. एमएस रंधावा ने एक लेख में किसानों और खेती के बारे में लोकप्रिय धारणा के बारे में बात की थी। एक किसान निस्संदेह बहुत मेहनती होता है। सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बारिश आती हो; आप हमेशा उसे खेतों में कड़ी मेहनत करते हुए देख सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसानों ने अपने श्रम से, पसीना बहाकर अकेले ही देश को भूख के जंजाल से बाहर निकाला है।

लेकिन डॉ. रंधावा को उस समय समाज में प्रचलित एक किसान की स्वीकृत छवि से परेशानी हुई। आमजन की कल्पना में, किसान एक सादी पोशाक पहनता है, अक्सर एक मैला कुर्ता व धोती पहनता है और टूटी-टांके लगी धूल-धूसरित जूती पहनकर चलता है। उम्मीद रहती है कि आने-जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा साइकिल इस्तेमाल करता है, और जब भी आप उसे दोपहिया वाहन चलाते हुए देखते हैं, तो अक्सर भौंहें तन जाती हैं। हालांकि अब वक्त बदल गया है लेकिन किसान और खेती के बारे में धारणा अब भी पूर्ववत ही कायम है।

साइकिल की जगह भले ही दोपहिया वाहन ले चुका है, जिसे अब कार द्वारा बदला जा चुका है, ऊपरी तबके में किसानों के पास कई बार शानदार मॉडल भी होते हैं, लेकिन एक पेशे के रूप में खेती के बारे में आमजन की सोच में बहुत बदलाव नहीं आया है। ग्रामीण-शहरी विभाजन का प्रतिबिंब, खेती अभी भी शहरी हाशिये पर बनी हुई है। मिसाल के तौर पर, यदि कोई किसान शहरी दायरे में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो उसे अभी भी नापसंद किया जाता है, और यहां तक ??कि खान-पान के तौर-तरीके अपनाता है, जिसमें मिसाल के तौर पर पिज्जा खाना भी शामिल है। इसके अलावा, ऐसे समय में जब एक घरेलू सहायिका को अपने कार्यस्थल तक जाने को स्कूटी चलाते हुए देखना असामान्य नहीं है, एक किसान द्वारा ट्रैक्टर पर महंगे म्यूजिक सिस्टम का उपयोग करना मंजूर नहीं है।

असल में, खेती एक दोयम दर्जा शब्द बन गया है। किसानों के प्रति इतनी गहरी उदासीनता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों पर सवाल उठाने वाले प्रबल वृत्तांत के साथ ही तिरस्कार और अवमानना ????का भाव भी सामने आता है। विरोध कर रहे किसानों पर लगातार अपमानजनक शब्द कहे जा रहे हैं और मुख्यधारा के माध्यमों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कृषक समुदाय के खिलाफ व्याप्त कुंठा के भावों का प्रतिबिंब हैं। आम तौर पर यह माना जाता है कि किसान बहुत पाला-पोसा जाता है, उन्हें भारी सब्सिडी व मुफ्त बिजली मिलती है, और वे इनकम टैक्स नहीं देते। किसानों की आय में कोई भी वृद्धि उपभोक्ता कीमतों पर असर डालेगी। जिसके परिणामस्वरूप खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ेगी इसलिए किसानों को बढ़ी हुई आय के अधिकार से वंचित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

चारों ओर इतनी गलत सूचनाएं, और त्रुटिपूर्ण आर्थिक तर्क उछाले जा रहे हैं कि मिथक व वास्तविकता में भेद करना आसान नहीं। किसी भी मामले में, नीति-निर्माता, अर्थशास्त्री और मीडिया फैलाए जा चुके भ्रम से खुश लगते हैं। चाहे वह काल्पनिक खाद्य मुद्रास्फीति के आंकड़े हों या राष्ट्रीय खजाने पर संभावित वित्तीय बोझ, सभी प्रकार के संदिग्ध आंकड़े प्रचलित हैं। मूल मान्यता यह है कि किसानों की आय में कोई भी बढ़ोतरी बाजार को बिगाड़ देगी और इससे व्यापार और उद्योग के मुनाफे में कमी आएगी। हकीकत में, जो स्वाभाविक से भी ज्यादा हो चुका है वह ये कि किसान को निरंतर गरीबी में रखने को लेकर देश संतुष्ट नजर आता है।

यदि किसान इतने लाड़ले होते तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि औसत कृषि आय निम्नतम स्तर पर बनी रहनी चाहिये थी। जो पहले कहा जा चुका है उसे दोहराने के जोखिम पर, कृषि परिवारों के लिए स्थितिजन्य आकलन सर्वेक्षण 2021 की नवीनतम रिपोर्ट की गणना के मुताबिक, कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये है। इससे यह भी पता चला कि खेती से होने वाली आय मनरेगा श्रमिकों की मासिक मजदूरी से भी कम थी। इससे भी बुरी बात, किसानों की स्थिति पर देश के एक अंग्रेजी दैनिक में बीती 23 फरवरी को प्रकाशित विवरण से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में औसत कृषि आय अभी भी कम है और 5,000 रुपये से 6,000 रुपये प्रति परिवार प्रति माह के बीच है। यहां तक ??कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी, जहां 90 प्रतिशत से अधिक किसान परिवार कर्जदार हैं, आय बहुत कम है। एक अध्ययन में यह पता चला है कि आंध्र प्रदेश के कई सूखा प्रभावित जिलों में लगभग 14 प्रतिशत पारिवारिक आय सरकारी योजनाओं से आती है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष आय मदद शामिल है।

इसके अलावा, जैसा कि कुछ दिन पूर्व पेश 2022-23 घरेलू खर्च सर्वेक्षण से पता चलता है कि एक पेशेगत उद्यम के रूप में खेती कितनी अनिश्चित हो गई है, जिसमें कृषि परिवारों का खर्च ग्रामीण परिवारों से कम हो गया है। आय कम होने के कारण उपभोग कम है। इसलिए यह कहना कि किसान आयकर नहीं देते, उचित नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम सबसे पहले किसानों को कर योग्य आय दें?

किसी भी स्थिति में, यह उपभोक्ता केंद्रित नजरिया ही है जो असल में किसान को सही कीमत प्रदान करने से इनकार करता है। एक-दो साल को छोड़ दें तो व्यापार की शर्तें नकारात्मक रही हैं। कई अध्ययनों में सामने आया कि एक दशक से ज्यादा वक्त से ग्रामीण मजदूरी स्थिर है या फिर घट रही है। कृषक परिवारों के उपभोग स्तर में गिरावट भी यह इंगित करती है। और फिर भी, जैसे ही उच्चतर एमएसपी घोषित किया जाता है, अखबारों के संपादकीय लगभग हर बार इसे खाद्य मुद्रास्फीति में प्रत्याशित बढ़ोतरी से जोड़ने लगते हैं।

दरअसल, कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी द्वारा जिन 23 फसलों के लिए एमएसपी की गणना करने के बाद उनकी कीमतों की घोषणा की जाती है, तो वह उनकी कीमतों की सिफारिश करने से पहले इनपुट-आउटपुट मूल्य समानता और बाजार कीमतों के रुझान पर गौर करता है। इसके अलावा, खाद्य मुद्रास्फीति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित जायज सीमा के भीतर रखने से, लोगों को अक्सर यह अहसास नहीं होता है कि किसान वास्तव में उपभोक्ताओं और इस तरह देश की अर्थव्यवस्था को सब्सिडी देते हैं।

देविंदर शर्मा

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी के हालिया अध्ययन बताता है कि भारतीय किसान साल 2000 से घाटे की खेती कर रहे हैं, जिस वर्ष इसने उत्पादक-सब्सिडी मदद का आकलन करना शुरू किया था। किसानों को जो आर्थिक नुकसान हुआ है वह मार्केट में किसानों को मिलने वाली कीमत और सब्सिडी, कुछ राज्यों में फ्री बिजली मदद भी, को जोड़ने के बाद हुआ है। ओईसीडी डेटा यह भरपूर स्पष्ट करता है कि बाजार को कायम रखने के लिए, हमने जान-बूझकर खेती को कंगाल बनाए रखा है।

जब तक हम किसान को मूलभूत जरूरतों से वंचित रखना जारी रखेंगे, तब तक डॉ. एमएस रंधावा द्वारा उकेरी गयी किसान की छवि बदलने वाली नहीं है। किसान को संकट से उबारने के लिए एमएसपी की गारंटी पहला कदम होगा, लेकिन उसे दशकों से हो रहे घाटे की पूर्ति करने के लिए और भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। जब तक किसानों और समाज के अन्य वर्गों के बीच आय में बराबरी यकीनी बनाने के प्रयास नहीं किये जाते तब तक किसान अपनी छवि से बाहर नहीं निकल सकता है।

# सरसो की आड़ में उगा रहे थे अफीम, पुलिस के कानों तक पहुंची बात

माही की गूंज, मंदसौर।

अफीम एक ऐसा नशा है, जिसको लेकर दुनिया के हर देश में अलग-अलग कानून बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा अफीम का अफगानिस्तान में उगाई जाती है। वहीं, मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच ज़िले भी अफीम उगाने में पीछे नहीं है।

यही नहीं, अफीम की अवैध खेती की ये रवायत अब डच् के बाकी ज़िलों में भी शुरू हो गई है...। क्योंकि जिस तरह से मैहर जिले से लगातार अफीम की अवैध खेती के मामले सामने आ रहे हैं उससे ऐसा ही लग रहा है कि अवैध करोबारी मैहर को मंदसौर बनाने में तुले हुए हैं। महज़ चौबीस घंटे के अंदर जिले में दो जगहों पर अफीम खेती पकड़ी गई।

### बीते दिनों भी सामने आया था मामला

बीते दिन, अमरपाटन थाना क्षेत्र के सुआ गांव के बाद अब बदेरा थाना क्षेत्र के ककरा हल्का के कुबरी गांव में अफीम की खेती पकड़ी गई थी। तो वहीं, मंगलवार देर रात पुलिस आरोपियों के खेत से अफीम उखड़वा दी। अभी तक इस मामले के आरोपियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। पर पुलिस सूत्रों ने बताया है कि, कोई जुगल किशोर पटेल है जिसे पुलिस ने पकड़ा है और यह अफीम की खेती भी उसी की है।

### मौके पर पहुंचीं पुलिस व राजस्व विभाग की टीम

कुबरी गांव में अफीम की खेती किए जाने का मामला सामने में आने के बाद नायब तहसीदार समेत बदेरा थाना एसएचओ अरुण सोनी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे। बताया जाता है कि, कुबरी हल्का की आराजी नंबर 33 में अफीम बोई पाई गई। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक इस जमीन का मालिक चंद्रभान सिंह, रामनिवास है। इस ज़मीन का क्षेत्रफल करीब 1.8500 हेक्टेयर है।

### सरसों की आड़ में बोई गई थी अफीम की फसल

यह अफीम की फसल सरसों की फसल के साथ बोई गई थी। ताकि किसी को भी इस बात का पता नहीं चल सके। हालांकि जब फसल तैयार हुई और अफीम की डोंडी बाहर आई उसके बाद गांव में चर्चा शुरू हो गई। अमरपाटन के सुआ गांव में कार्रवाई के बाद चर्चा ने जोर पकड़ा और मामला पुलिस विभाग तक जा पहुंचा।

# लैला ने छोड़ा मजनू का साथ, समाजसेवियों ने किया अंतिम संस्कार

माही की गूंज, मंदसौर।

शहर की सड़कों पर दिखने वाला लैला मजनू का जोड़ा सोमवार शाम को बिछड़ गया। इसका अंतिम संस्कार समाजसेवी व पार्षद सुनील बंसल ने मंगलवार को विधि विधान से किया। मंदसौर शहर की सड़कों पर दिखने वाला एक ऐसा जोड़ा जिसे लोग पिंकी लालवानी (लैला) और अमित शर्मा (मजनू) के नाम से जानते थे। जो लंबे समय से एक-दूसरे के साथ रह रहे थे। लेकिन सोमवार की शाम पिंकी का निधन हो गया। इसकी सूचना पड़ोसियों ने सुनील बंसल को दी, जिसके बाद सुनील बंसल ने पिंकी के भाइयो को पिंकी के निधन की जानकारी दी और अंतिम संस्कार करने की कहा लेकिन पिंकी के भाइयो ने पिंकी का अंतिम संस्कार करने से इंकार कर दिया। इसके बाद बंसल ने मंगलवार सुबह पिंकी का अंतिम संस्कार करने की बात कही। मंगलवार सुबह सुनील बंसल ने नगरपालिका के हेमंत शर्मा और जाकिर भाई को मामले से अवगत करवाया और शव वाहन और नगरपालिका कर्मी भेजने को कहा।

सुनील बंसल अंतिम संस्कार की सभी सामग्री लेकर कुम्हारवाड़ा में पिंकी और अमित के निवास स्थान पर पहुंचे और वहा से पिंकी को शव वाहन द्वारा मुक्तिधाम ले जाया गया। मुक्तिधाम पर समाजसेवी बंसल ने विधि विधान के साथ पिंकी का अंतिम संस्कार किया। मृतक पिंकी लालवानी मंदसौर के महाजन मोहल्ला जनकूपुरा की निवासी थी, जिसे लोग करिश्मा भी कहते थे। पिंकी ने एलएलबी भी कर रखी थी। परिजन के निधन के बाद पिंकी की मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी और पिंकी के भाइयो ने उसे घर से अलग कर दिया था। इसके बाद पिंकी अमित शर्मा (मजनू) जो कि दिव्यांग है के संपर्क में आई और कई वर्षो से दोनों साथ रह रहे थे। अमित और पिंकी दोनों हमेशा एक-दूसरे का हाथ पकड़े शहर की सड़कों पर घूमते मिलते थे और शाम को गांधी चौराहे पर दोनों सेवा बैंक में भोजन करने आते थे। लेकिन कुछ दिनों से पिंकी ने आना बंद कर दिया था। अमित उसका भोजन भी अपने साथ ले जाकर पिंकी को खिलाता था। दोनों मानसिक रूप से कमजोर जरूर थे, लेकिन दोनों में अटूट प्रेम था जिसके कारण दोनों को लोग लैला मजनू के नाम से जानते थे।

# नगरपालिक निगम आयुक्त पर को तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड

माही की गूंज, रतलाम।

मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार प्रदेश के विकास के लिए बिना रुक लगातार काम कर रही है। वहीं इसके साथ ही सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था भी बनाई हुई है और कानून तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। फिर चाहे गलती करने वाला शख्स आम इंसान हो या फिर कोई सरकारी अधिकारी, जिसने कानून तोड़ा उसे सजा मिलना तय है। हाल ही में गंभीर अनियमितता करने के लिए रतलाम नगरपालिक निगम आयुक्त अखिलेश गहरवार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

### अखिलेश गहरवार को निलंबन आदेश जारी

पिछले कुछ दिनों से अखिलेश गहरवार के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें आ रही थीं। जब मामला नगरीय विकास और आवास विभाग के नजर में आया तो तुरंत विभाग ने इस पर सख्त एक्शन लेते हुए काम गंभीर अनियमितताओं के लिए रतलाम नगरपालिक निगम आयुक्त अखिलेश गहरवार को निलंबन संबंधी आदेश जारी कर दिया। आयुक्त अखिलेश गहरवार को निलंबन अवधि के दौरान हर रोज उज्जैन के गरीय प्रशासन एवं विकास के मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक को रिपोर्ट करना होगी।

### जांच में क्या निकला...?

जांच रिपोर्ट के मुताबिक रतलाम में सिविल सेंटर के 22 प्लाटों की रजिस्ट्री अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर की गई थी, जिनके नाम कूटरचित तरीके से संपादित (एडिट) किए गए थे। इसी की वजह से इन नामों के साथ रजिस्ट्री के पहले एमआईसी और परिषद से सामने इन्हें अनुमति दी गई थी। इसके अलावा जांच रिपोर्ट में अखिलेश गहरवार की कई और गंभीर अनियमितताएं भी सामने का बारे में खुलासा किया गया।

# बार-बार बदल रहा मौसम, लोगों की सेहत पर पड़ रहा असर

माही की गूंज, शाजापुर।

पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव है। दोपहर के समय धूप रहती है और सुबह शाम व रात को सर्दी। मौसम के इस मिजाज से सेहत पर विपरीत असर पड़ रहा है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है।

चिकित्सकों का कहना है कि, बीमारियों से बचने के लिए खानपान और पहनावे का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। मौसम में हुए बदलाव के कारण सर्दी खांसी जुकाम और बुखार की समस्या लोगों को हो रही है। हालांकि लंबे समय तक ठिठुराने वाली सर्दी का मौसम अब विदाई की बेला में है। अधिकतम तापमान जहां 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है तो वहीं रात का तापमान भी 12 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच चुका है।

पिछले कुछ दिनों से तापमान कभी कम तो कभी ज्यादा हो रहा था, लेकिन अब तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी है। मौसम का यही बदलाव सेहत पर विपरित असर डाल रहा है। पिछले तीन दिनों में तापमान में चार डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि हुई है। मौसम पर्यवेक्षक सत्येंद्र धनोतिया ने बताया कि अब गर्मी का मौसम दस्तक दे चुका है।

### ऐसे रखें बच्चों का ख्याल

चिकित्सकों का कहना है कि, मौसम में आए परिवर्तन का प्रभाव बच्चों पर सर्वाधिक पड़ता है। बच्चे जल्दी ही बुखार, सर्दी- खांसी के साथ ही मौसमी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए। ताकि मौसम के बदलाव का असर उनकी सेहत पर न पड़े। इसके लिए खानपान से लेकर उनके कपड़ों तक हर चीज को लेकर सतर्कता जरूरी है।

### झोलाछाप डॉक्टर के यहां मरीजों की भीड़

जिला मुख्यालय शाजापुर सहित जिले के गांव शहरों में झोलाछाप डॉक्टर काफी मजे में हैं। स्वास्थ्य विभाग की कृपा से इनका कारोबार जमकर चल रहा है। मौसम के बदलाव से स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित लोग इनके पास ही जा रहे हैं। छोटी-मोटी समस्याओं में तो इनके पास जाने से लाभ हो रहा है। किंतु गंभीर समस्या होने पर यहां आना हानिकारक भी साबित हो रहा है।

कुछ मामले ऐसे भी सामने आ चुके हैं, जो क्लीनिक दवाखाना पर उचित उपचार नहीं मिलने के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्या के शिकार हो गए। झोलाछाप डॉक्टरों के यहां नियम कायदों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। यहां झोलाछाप बिना योग्यता लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बावजूद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसका लाभ भी झोलाछाप डॉक्टरों को मिल रहा है।

# यहां खीर की प्रसाद को ग्रहण करने से नि:संतान दंपत्ति को हो जाती है संतान की प्राप्ति...!

माही की गूंज, रतलाम।

जिले के बिलपांक स्थित विरुपाक्ष महादेव मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित प्राचीन कालीन मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार हर साल यहां महाशिवरात्रि के बाद अमावस्या पर मंदिर प्रांगण में हवन कुंड के ऊपर मटके में चावल पकाए जाते हैं। जो कि हवन कुंड की अग्नि से पकते है। बाद में उसकी खीर बनाकर निसंतान दंपतियों को प्रसाद के तौर पर दी जाती है। मान्यता के अनुसार गोद भरने के बाद वह अगले साल भगवान विरुपाक्ष महादेव मंदिर में अपनी संतान के साथ दर्शन करने आते हैं और मंदिर प्रांगण में उन्हें मन्नत अनुसार तोला जाता हैं।

### बहुत खास है विरुपाक्ष महादेव मंदिर

रतलाम में स्थित विरुपाक्ष महादेव मंदिर परमार और चालुक्य स्थापत्य शैली के मिश्रण से बना हुआ है। धार्मिक स्थल के साथ यह एक पर्यटन स्थल भी है। मंदिर के चारों कोनों पर एक-एक लघु मंदिर निर्मित है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और इसका एक स्तंभ अन्य स्तंभों से अलग है। शिवलिंग के चारों ओर मंडप में चार अलंकृत स्तंभ स्थित हैं।

### खीर को माना जाता है महाप्रसाद

हर वर्ष महाशिवरात्रि के बाद अमावस्या के दिन बांटे जाने वाली खीर को यहां का महाप्रसाद माना जाता है। वर्षो से चली आ रही मान्यता के अनुसार इस खीर के प्रसाद को ग्रहण से निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति हो जाती है।

### सड़क दुर्घटना में युवती की मौत

माही की गूंज, रतलाम। जिले के शिवगढ़ थाने पर प्रवीण पिता हूरसिंग गरवाल निवासी जूनी बोयडी हाल मुकाम जवाहर नगर रतलाम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि, बाजना-शिवगढ़ रोड़ स्थित ग्राम छावनी झोडिया के पास लोडिंग टेम्पो वाहन क्रमांक एमपी 43 जी 4817 के चालक ने वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसकी मोटर साइकल को टक्कर मार दी। जिससे बाइक पर पीछे बैठी 22 वर्षीय लक्ष्मी पुत्री निर्मल डोडियार निवासी चंद्रगढ़ थाना बाजना की मृत्यु हो गई और वह घायल हो गया। पुलिस ने लोडिंग वाहन चालक के खिलाफ धारा 279, 337, 304 ए भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया।

# ढोल प्रथा को निखारने प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

माही की गूंज, बरझर।

जनपद वार्ड क्रमांक 1 बरझर के सदस्य कालू वसुनिया द्वारा ढोल प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय वानखेड़े स्टेडियम में करवाया गया। जिसका प्रथम इनाम 11 हजार रुपए व दुसरा स्थान द्वितीय इनाम 5 हजार रुपए रखा गया था। बरझर क्षेत्र में पहली बार हो रही ढोल प्रतियोगिता को लेकर जनपत पंचायत क्षेत्र के 50 से अधिक टीम ढोल मांदल लेकर मैदान पहुंची। सबेरे से ढोल आना चालू हो गये थे जो शाम 4 बजे तक अपने-अपने ढोल मांदल कि थाप पर नजरा देखने वाले निहारते रहे। इधर आयोजनकर्ता कालू वसूनिया ने अंतिम समय गुजरात राज्य के धानपुर को पहले स्थान के रूप में 11 हजार रुपए व बरझर के राठोड़ी फलियां को दुसरा स्थान 5 हजार रुपए इनाम स्वरूप दिए। कालू वसुनिया ने इस प्रतियोगिता को लेकर कहा कि, जो ढोल की प्रथा धीरे-धीरे बंद होती जा रही है उसे फिर एक बार निहारा जाए ओर परम्परा बनी रहेगी। भगोरिया पर्व के पहले ऐसे आयोजनों से भगोरिया कि उमंग ओर बढ़ती है समाज में उत्साह का माहोल बनता है।

### लोकसभा प्रत्याशी अनीता चौहान भी पहुंची

बरझर वानखेड़े स्टेडियम में ढोल? मांदल प्रतियोगिता आयोजित में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अनिता चौहान भी पहुंची। जिससे ढोल मांदल प्रतियोगिता में शामिल लोगों में उत्साह का माहोल नजर आया। साथ ही अनिता चौहान ने ढाल मांदल गुप से चर्चा कर होली भगोरिया पर्व की बधाई शुभकामनाए भी दी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष मकू पोरवाल, सांसद प्रतिनिधि विशाल रावत, जनपद पंचायत अध्यक्ष इन्दरसिह डावर, भूपेंद्र डावर, मण्डल अध्यक्ष लालसिंह चोहान, रिगोल सरपंच महेश भूरिया, बोरकुणडिया सरपंच विक्रम ढाक आदि मौजूद थे।

# खाटूश्याम बाबा की भव्य फाग यात्रा 17 को, सनातन सर्वसमाज की बैठक संपन्न

माही की गूंज, मंदसौर।

17 मार्च रविवार को नगर में खाटूश्याम बाबा की भव्य फाग यात्रा धूमधाम से सभी धर्म प्रेमियों द्वारा निकाली जाएगी। फाग यात्रा को लेकर सनातन सर्वधर्म सर्वसमाज की एक विशेष बैठक रविवार को हीरा की बगीची में पूज्य गुरूदेव आशीष जी शर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। जिसमें उपस्थित सभी महानुभावों ने अपने-अपने सुझाव यात्रा हेतु दिए।

श्री श्यामसखा मित्र मंडल मंदसौर ने बताया कि, फाग यात्रा में भक्तजन बाबा के साथ गुलाल की होली खेलेगे। फाग यात्रा का विषेष आकर्षण बाबा की शाही सवारी रहेगी। वहीं दिल्ली की झांकियां, राधा कृष्ण झांकी, अघोरी नाथ की झांकी, राम मंदिर की झांकी, उज्जैन के ताशे, मंदसौर के ताशे, उज्जैन की डमरू पार्टी, महाकाल की तोप, डीजे, घोड़े, बग्घी, अन्नपूर्णा ढोल पार्टी, फूल वर्षा, इत्र वर्षा आदि आकर्षण का केन्द्र रहेंगे और सबसे प्रमुख आकर्षण 3 हजार किलो गुलाल की होली होगी, जो कि सभी प्रेमी बाबा के साथ खेलेंगे।

श्री श्यामसखा मित्र मंडल मंदसौर ने सभी धर्मप्रेमियों से निवेदन किया है कि, शहर के सभी समाज, सभी वर्ग, श्याम बाबा की फाग यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें अपने मित्रों रिश्तेदारों को भी मंदसौर यात्रा में बुलाएं।

# बैंक सखी बनकर लखपति हुई जिले की संजू

माही की गूंज, शाजापुर।

**किसी भी समाज को सशक्त बनाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध हों। महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना समृद्ध समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। मध्यप्रदेश की महिलाएं आज स्वावलंबन के रास्ते पर चलकर खुद की आजीविका स्थापित करने में सफल हुई हैं। यह सब संभव हुआ है ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बनाए गए स्व-सहायता समूहों से। इन समूहों से जुड़कर महिलाओं ने खुद को और अपने परिवार को भी आर्थिक मजबूती दी है। ऐसी ही एक सशक्त महिला हैं शाजापुर जिले की ग्राम पंचायत गोविंदा निवासी संजू मालवीय। यह जानकारी सोमवार को जनसम्पर्क अधिकारी घनश्याम सिरसाम ने दी।**

संजू बताती हैं कि, वह पढ़ लिखकर कामकाज से जुड़ना चाहती थीं, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ज्यादा दिनों तक स्कूल नहीं जा पाईं और कक्षा 9वीं के बाद उसकी शादी हो गई। ससुराल आई, तो उनके पति ने पढाई के लिए प्रेरित किया। पति की प्रेरणा से संजू ने आगे की पढ़ाई की और बीए पास कर लिया।

### अब खुशहाल जीवन जी रहा है परिवार

संजू ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने कुछ काम करने का सोचा, इससे परिवार को मदद मिले। लेकिन कोई राह नहीं सूझ रही थी। तभी उनको स्व-सहायता समूह के बारे में पता चला। आजीविका मिशन द्वारा संजू को बैंक सखी के रूप में चुना गया। बैंक सखी बनकर लोगों से जुड़ने के बाद संजू का आत्मविश्वास बढ़ा और वह दूसरे कामों के लिए आगे बढ़ने लगी। संजू ने आजीविका एक्सप्रेस के माध्यम से एक वाहन खरीदा और इसे चलाने के लिए अपने पति को दे दिया। इससे उसकी आय और बढ़ी। आजीविका एक्सप्रेस से उसके पति को हर महीने सात हजार रुपये मिलने लगे। लगभग इतना ही संजू भी कमाने लगी। इससे पति-पत्नी की सालाना आय एक लाख से भी अधिक हो गई है। अब संजू और उसका परिवार खुशहाल जीवन जी रहे हैं। संजू की प्रगतिशीलता के लिए उसे जिला स्तर पर सम्मानित किया गया।

### 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिली मदद

महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए शुरू किए गए आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों से अब तक देश की 10 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं। इन महिलाओं को समूहों के जरिये 100 तरह की अलग-अलग गतिविधियों के संचालन के लिए सरकार से बैंक लिंकेज दिलाकर स्वरोजगार ऋण दिया जाता है। मध्यप्रदेश में करीब पांच लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों से जुड़कर लगभग 61 लाख से अधिक परिवार अपनी आय बढ़ाकर अब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। स्व-सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं खुद की आजीविका चलाने में भी सक्षम होकर सबला हुई हैं।

# आज जिले में विकास की सौगात देंगे सीएम यादव

माही की गूंज, खरगोन।

**मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय के कैम्पस का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे खरगोन जिले के 571 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे।कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।**

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा बैठक में समस्त शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को निर्देशित किया गया कि इस कार्यक्रम में उनकी संस्था के अधिक से अधिक विद्यार्थी उपस्थित होकर निमाड़ क्षेत्र की इस उपलब्धि के सहभागी बने।

पीजी कॉलेज में क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय के शुभारंभ अवसर पर जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहेंगे। खरगोन में इस विश्वविद्यालय के प्रारंभ होने से शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति का संचार होगा। कलेक्टर श्री शर्मा ने इस विश्वविद्यालय के लिए 150 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है। यह भूमि खरगोन कसरावद रोड के पश्चिम में मेनगांव, दारापुर, नारायणपुरा तथा किशनपुरा की सीमा से लगी हुई होगी।

बैठक में कार्यक्रम स्थल पर छात्र-छात्राओं की बैठक व्यवस्था एवं लोकार्पण किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि कार्यक्रम स्थल पर इस तरह की व्यवस्था की जाए कि छात्र-छात्राओं को आने में किसी तरह की परेशानी न हो। विश्वविद्यालय कैम्पस के शुभारंभ अवसर पर पीजी कॉलेज खरगोन, कन्या महाविद्यालय खरगोन, पॉलिटेक्निक कॉलेज खरगोन, लॉ कॉलेज खरगोन, पैरामेडिकल कॉलेज खरगोन, मण्डलेश्वर, कसरावद, बड़वाह, सनावद, भीकनगांव, झिरन्या, बेड़िया एवं भगवानपुरा के सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय के छत्र-छात्राएं उपस्थित रहेंगे।

खरगोन में विश्वविद्यालय प्रारंभ होने से इसमें नये-नये कोर्स एवं अनुसंधान के कार्य प्रारंभ होंगे। जिससे इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए इंदौर एवं अन्य बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय के खुलने से खरगोन जिले में शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर भी पैदा होंगे। लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला यह विश्वविद्यालय छात्रों के समग्र विकास के लिए विश्व स्तरीय अधोसंरचना प्रदान करेगा।

क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय में खरगोन, बड़वानी, आलीराजपुर, खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले के 83 शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों को शामिल किया जाएगा। इन महाविद्यालयों के लगभग 25 हजार छात्र-छात्राएं इस नये विश्वविद्यालय के अधीन उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे।

# सरकारी नौकरी छोड़कर गजेंद्रसिंह को टक्कर देंगे पोरलाल खरते

माही की गूंज, खरगोन। ब्रजभूषण दसौंदी

देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसमें कई चेहरे हैरान करने वाले हैं। खरगोन-बड़वानी संसदीय सीट से सेल टैक्स विभाग से वीआरएस लेकर सक्रिय राजनीति में आए युवा पोरलाल खरते को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस से टिकट के लिए पूर्व विधायक पानसेमल व पूर्व मंत्री वाला बच्चन के ग्यारसीलाल रावत भी दावेदार थे।

कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते।

पोरलाल का भाजपा के प्रत्याशी व सांसद गजेंद्र सिंह पटेल से मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी ने गजेंद्र सिंह को दूसरी बार मैदान में उतारा है। जबकि खरते पहली बार चुनाव में अपना भाग्य जमाएंगे। आदिवासी समाज में जल, जंगल व जमीन के साथ संवैधानिक अधिकारों को लेकर लंबे समय से सक्रिय हैं।

भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल।

विधानसभा 2023 के चुनाव में संसदीय क्षेत्र की 8 में से 5 सीटों पर बढ़त बनाने से कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। जबकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पटेल ने पिछला चुनाव 2 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीता था।खरते चुनावी राजनीति में नए हैं। उन्हें संगठनात्मक रूप से चुनाव के लिए जमावट करनी होगी।

### वर्चस्व की है लड़ाई

अनुसूचित जनजाति बहुल सीट इस पर आदिवासी मतदाताओं को अपने पक्ष में लाना दोनों ही उम्मीदवारों के लिए बड़ी चुनौती होगी। सांसद पटेल अनुभवी है, इसका उनको फायदा मिलेगा। संवैधानिक अधिकारों को लेकर खरते आदिवासियों के बीच में चर्चित है। पोरलाल खरते यूथ कांग्रेस से भी जुड़े थे। अरुण यादव और भूरिया परिवार से उनके अच्छे संबंध माने जाते हैं।

# लारेंस विश्नोई गिरोह को हथियार सप्लाई के मामले में एनआइए की दबिश

माही की गूंज, बड़वानी/खरगोन।

माफिया लारेंस विश्नोई गिरोह और खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन को हथियारों की सप्लाई के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने मध्य प्रदेश सहित चार राज्यों में लगभग 30 ठिकानों पर छापेमारी की है। मध्य प्रदेश में बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर में संदिग्धों के घरों में छापा मारा गया है। तीनों जिलों में एक-एक थाना क्षेत्र में कार्रवाई चली।

इसके लिए एनआइए की दो अलग-अलग टीमें लगी रहीं। बताया जा रहा है कि हरियाणा के रोहतक में एक व्यापारी की हत्या के बाद तीन बाल अपचारी गिरफ्तार किए गए थे। उनसे पूछताछ से मिली सूचना के आधार पर एनआइए ने चारों राज्यों में एक साथ छापेमारी की है। इसमें गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई गैंग के जुड़ाव होने का संदेह है। एनआइए की टीम ने खरगोन के भगवानपुरा और गोवाना गांव में छापेमारी की। यहा बड़ी संख्या में सिकलीगर रहते हैं। यह क्षेत्र अवैध हथियार बनाने और सप्लाई करने के लिए जाना जाता है। एनआइए ने बड़वानी के खडकी गांव में भी एक युवक से पूछताछ की थी। उससे पूछताछ के बाद जांच एजेंसी की टीम ने उमरती गांव में भी हथियार सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति की तलाश में पहुंची।

बीते छह माह में एनआइए ने इस क्षेत्र में दूसरी बार छापेमारी की है। खालिस्तानी आतंकी, गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा और अवैध हथियार बनाने और सप्लाई करने वालों के गठजोड़ वाले पूरे नेटवर्क पर एनआइए पिछले कई माह से कार्रवाई कर रही है।

### मोबाइल नंबरों की पड़ताल के लिए संदिग्धों के ठिकानों पर पहुंची एनआइए

हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ, आरोपितों और संदिग्धों के बीच बातचीत में सामने आए मोबाइल नंबरों के आधार पर और इनकी पड़ताल के लिए एनआइए तीनों जिलों में पहुंची थी। सूत्रों ने बताया के जो मोबइल नंबर हथियार सप्लाई में उपयोग किए जा रहे हैं वह सिम अन्य लोगों के नाम पर है।

### वन कन्या आश्रम में किया मासिक स्वास्थ्य परीक्षण

माही की गूंज, उदयगढ़।

शासकीय कन्या आश्रम अंबा खेड़ी में मासिक स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया। इस तरह के परीक्षण का आयोजन अनुविभागीय अधिकारी की देखरेख में के समस्त छात्रावास एवं आश्रम में आयोजित किए जाएंगे। जिसका मुख्य उद्देश्य एनीमिया मुक्त अलीराजपुर के लक्ष्य को प्राप्त करना है। साथ ही कुपोषण की वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त करना ताकि आगामी दिवसों में प्रयास कर पोषण अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किया जा सके।

# आदिवासी व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला, दो लोग हिरासत में

माही की गूंज, बड़वानी।

मध्यप्रदेश में आदिवासियों के साथ मारपीट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बड़वानी का है। यहां एक दुकानदार ने आदिवासी दंपती से बदसलूकी की। पति को बीच बाजार में पीटा। बचाने आई पत्नी को धक्का दिया। घटना मंगलवार देर शाम की है। इसका वीडियो आज सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित पक्ष को शिकायत करने के लिए बुधवार को थाने बुलवाया गया है।

### आदिवासी के साथ गाली-गलौज भी की

बड़वानी में बस स्टैंड के पास रितेश वर्मा की पान की दुकान है। उसका आदिवासी दंपती से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद उसने मारपीट शुरू कर दी। आरोपी के साथी ने दंपती के साथ गाली-गलौज की। इसके बाद आदिवासी व्यक्ति के साथ मारपीट की। जिसका वीडियो वहां मौजूद किसी ने बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा।

### सीएम और कमिश्नर से कड़ी कार्रवाई की मांग

जयस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर लोकेश मुजाल्दा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कमिश्नर को टैग कर उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आदिवासी समाज के कई सामाजिक संगठनों ने घोर निंदा कर सोशल मीडिया के माध्यम से गैर आदिवासी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वीडियो वायरल के संबंध में वीडियो के आधार मारपीट करने वाले युवक व एक अन्य को हिरासत में लिया है। शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

# नवीन बस को डावर ने नारियल फोड़कर किया रवाना

माही की गूंज, च.शे. आजाद नगर

चंद्रशेखर आजाद नगर (भाबरा) से नीमच बस सेवा प्रारंभ हुई, जिसका शुभारंभ पूर्व विधायक माधवसिंह डावर ने नारियल फोड़कर बस को नीमच के लिए रवाना किया। चशे आजाद नगर (भाबरा) से रतलाम बस सेवा को लेकर बड़े दिनों से बस मालिकों से मांग करते आ रहे थे कि रतलाम, मंदसौर बस प्रारम्भ करने से आमजनों को काफी सुविधा होगी। जिसे लेकर बस मालिक आसूतोश पंचोली ने आमजनता कि समस्या को ध्यान में रखते हुए बुधवार से पंचोली बस का शुभारंभ पूर्व विधायक माधवसिंह नारियल फोड़कर बस को रवाना किया। पहले ही दिन एक दर्जन सवारी लेकर बस रवाना हुई। इस अवसर पर माधवसिंह डावर ने कहा कि, रतलाम नीमच जाने के लिए दाहोद ट्रेन का सहारा लेना पड़ता था पंचोली बस के चालू होने से आवागमन सुविधा होगी। आजाद नगर भाबरा से 12.05 बजे रवाना होकर 5.30 बजे रतलाम व नीमच 9.30 बजे पहुंचेगी नीमच से सबरे 10.35 से चलकर थांदला 5.20 बजे व भाबरा 8.15 बजे पहुंचेगी जिससे आवागमन में सुविधा होगी।

# शिवालय से शिवजी की पीतल से बनी भारी प्रतिमा चोरी

माही की गूंज, आम्बुआ।

चोरी करने वालों की नियत कभी साफ नहीं हो सकती यदि होती तो वह चोरी ही नहीं करता चोरों की लालच देखिए कि, ग्राम में जो मंदिर से कई सामानों को चुराने के बाद भगवान की प्रतिमा को भी उठा ले गया। जिसकी लिखित शिकायत थाने पर की गई है।

आम्बुआ हथनी नदी किनारे स्थित अति प्राचीन शिवालय में कोरोना काल में कोई अज्ञात शिव भक्त पीतल से बनी लगभग 1 किलो वजनी शिव प्रतिमा जो की अलौकिक प्रतिमा थी जिसके आठ हाथ तथा बाघाम्बर पर विराजित प्रतिमा को विगत वर्षों से शिव भक्त पूजते आ रहे थे। बाल शिव भक्त मंडल के बाल शिव भक्त उन्हें पौलिश कर चमका कर रखते थे। इस शिव प्रतिमा से सबको अगाध श्रद्धा थी मंगलवार को दोपहर अज्ञात चोर प्रतिमा उठा ले गया। जिसकी जानकारी शाम को प्रदोष काल में बाल शिव भक्त मंडल जब पूजा आरती करने गए तब पता चला। इसके बाद खोजबीन की गई मगर जब कोई पता नहीं चला तो थाने पर लिखित सूचना बाल शिव भक्त मंडल तथा पुजारी की ओर से की गई है। स्मरण रहे की कुछ दिन पूर्व एक पीतल का त्रिशूल तथा तांबे का लोटा भी मंदिर से गायब हो चुका है। शिव भक्तों में दसशत व्याप्त है कि ऐसा कौन है जो मंदिर को निशाना बना रहा है उसे भगवान से भी डर नहीं लग रहा।

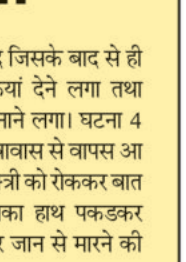

## बाबादेव की डूंगर पर शिव परिवार और हनुमान जी की हुई प्राण प्रतिष्ठा

माही की गूंज, बरझर।

तंबोलिया फलिया बाबादेव? की डूंगर पर तीन दिवस से चल रहें प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन में शिव परिवार और हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा की गई। सोमवार से बुधवार तक पांच कुंड हवन भी किया गया जिसमें श्रधालुओं ने बढ़ चढ़कर कर हिस्सा लिया। इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्स्व के पूर्णाहुति के बाद महाआरती की गई बड़ी संख्या में श्रद्धालुओ में भाग लिया। इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अनीता चौहान भी कार्यकताओं के साथ पहुंची ओर आरती में शामिल होकर भंडारे की प्रसादी ग्रहण की। साथ? ही पूर्व विधायक माधवसिंह डावर भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे ओर? प्रसादी ग्रहण कर भगवान शिव हनुमान से आशीर्वाद लिया। इस तीन दिनों से चल? रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में बरझर क्षेत्र के रिगोल, बोरणडिया, बड़गांव, महेन्दा, बड़ा खुटाजा, सहित गुजरात राज्य के श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रसादी ग्रहण कर भंडारा की प्रसादी का ग्राम के धर्म प्रेमियों ने लाभ लिया। इस आयोजन को लेकर लोधेश्वर महादेव समिति द्वारा सफलता कार्यक्रम को अंजाम दिया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष मक्कू पोरवाल, जनपद अध्यक्ष इन्दरसिह डावर, सांसद प्रतिनिधि विशाल रावत, भूपेंद्र डावर, अभिषेक मोटी डावर, मण्डल अध्यक्ष लालसिंह चौहान, विक्रम ढाक, हिमसिग बारीया, सरपंच महेश भूरिया, नटवर लाल, सोमला, विरसिह, बाबू, कालू वसूनिया आदि विशेष रूप से मौजूद थे।

# बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड

माही की गूंज, बड़वानी।

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव ने अपने एक फैसले में अभियोत्री के साथ बलात्कार करने के आरोपी राजु पिता घिसिया अजनारे, ग्राम बिलवानी, तहसील राजपुर को 10 वर्ष की कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से न्यायालय में पैरवी अपर लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने की।

उन्होंने बताया कि, 21 सितम्बर 2023 को अभियोक्त्री किराना सामान लेने के लिए अकेली बाजार गई थी, जब वह बाजार से वापस आ रही थी तो रास्ते की सुनसान जगह पर कपास के खेत में आरोपी मिला तथा उसने पशु के चारे का गट्ठर उठाने में सहयोग करने का कहा। जिस पर अभियोक्त्री उसकी बातों में आ गयी और मदद करने के लिए चारे का गट्ठर उठवाने के लिए कपास के खेत की मेड़ पर आ गई।

इस पर आरोपी राजु अजनारे ने जबरदस्ती बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर खींचकर उसे कपास के खेत में ले गया, वह चिल्लायी लेकिन आसपास सुनसान होने से किसी ने नहीं सुना। कपास के खेत में ले जाकर आरोपी राजु ने अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती बलात्कार किया। घटना के समय अभियोक्त्री जोर-जोर से चिल्ला रही थी जिस पर गांव कि अन्य महिला के आ जाने पर आरोपी वहां से भाग गया।

पुलिस राजपुर द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 506 (2) भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को बलात्कार की धारा 376 भादवि के तहत दोषी मानते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोत के मार्गदर्शन में प्रकरण में अनुसंधान तत्कालीन सहायक निरीक्षक आशा बामनिया द्वारा किया गया।

# नाबालिग पीड़िता से छेडछाड कर मारपीट करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की जेल एवं 3 हजार रुपए जुर्माना

माही की गूंज, बड़वानी।

विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने अपने फैसले में आरोपी नेपाल पिता फुलसिंह को धारा 354 भादवि एवं धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 3-3 वर्ष का कठौर कारावास एवं धारा 11/12 पाक्सो एक्ट में 1 वर्ष के कारावास एवं धारा 323 भादवि में 03 माह का कठौर कारावास एवं कुल 3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी दुष्यंतसिंह रावत एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बडवानी एस.एस. अजनारे द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि, घटना दिनांक से एक वर्ष पूर्व अभियोक्त्री की किसी रिश्तेदार की शादी में अभियुक्त से मुलाकात हुई थी और दानो की मोबाइल पर बात होती थी अभियोक्त्री के माता पिता के समझाने पर अभियोक्त्री ने अभियुक्त से बातचीत बंद कर दि जिसके बाद से ही अभियुक्त उसे परेशान कर धमकियां देने लगा तथा जबरदस्ति बात करने का दबाव बनाने लगा। घटना 4 नवम्बर 2023 को अभियोक्त्री छात्रावास से वापस आ रही थी, तब अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को रोककर बात नही करने पर बुरी नियत से उसका हाथ पकडकर छेडखानी करने लगा व मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।

छात्रावास अधीक्षक द्वारा समझाने पर अभियुक्त ने अधीक्षक सामने ही दो झापड मारे। 5 नवम्बर 2023 को भी अभियुक्त छात्रावास में आया था तथा अभियोक्त्री के नही मिलने पर तेजाब फेकने की धमकी देने लगा डर के मारे अभियोक्त्री उसके गांव चली गयी थी किंतु अभियुक्त उसका पिछा करता था जिसकी अभियोक्त्री ने परिवार वालो के साथ उक्त घटना की थाना रिपोर्ट पाटी पर दर्ज करवायी। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

# दिव्यांगों की हितेषी सरकार का दृष्टिबाधित बच्चों से कोई सरोकार नहीं?

## जर्जर भवन व अपर्याप्त सुविधाओं में रहने को मजबूर दिव्यांग

माही की गूंज, चं.शे. आजाद नगर। फिरोज खान

जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए चंद्रशेखर आजाद दृष्टिहीन पुनर्वसन केंद्र का संचालन किया जा रहा है। बरसो पूर्व बने भवनों की हालत अत्यधिक ख़राब खस्ता होने के चलते दृष्टिबाधित छात्र काफ़ी परेशानियों का सामना कर रात गुजारने को मजबुर रहते है। वर्तमान में दृष्टिहीन पुनर्वसन केन्द्र दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। इस केंद्र में कभी 50 से अधिक दृष्टिहीन बच्चे अध्ययनरत थे लेकिन वर्तमान में सिर्फ 15 छात्र से ही सिमटकर रह गया है। छात्रों के कम होने की खास वजह सुविधाओं की कमी के साथ ही कमरों की जर्जर हालत में भवन की स्थिति जो वषो पूर्व बने भवन खस्ताहाल में है। अन्दर उठते, बैठते, सोते वक्त ऐसा लगता है कहीं छत गिर न जाए। परन्तु इस दृष्टिहीन छात्रों की चिंता न तो प्रशासन को है न ही शासन को, गरीब तबके के बच्चे असुविधाओं में ही रहने को मजबूर हैं। बरसात के मौसम में छत से पानी टपकने के चलते छात्र सो भी नहीं पाते। साथ ही बच्चों के भरण-पोषण के लिए आने वाली राशि 10 वर्ष से नहीं बढ़ाई गई है। इसके चलतें संस्था को चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मध्यप्रदेश की शाखा इंदौर 2 द्वारा संचालित एवं सामाजिक न्याय व एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस केंद्र की स्थापना मध्यप्रदेश के पहले आदिवासी दृष्टिहीन पुनर्वसन केंद्र के रूप में वर्ष 1984 में हुई थी। यहां पर दृष्टिहीनों की प्रारंभिक शिक्षा प्रशिक्षण एवं पुनर्वसन के लिए जानी जाती है। वर्तमान में ना सिर्फ यहां बच्चों की संख्या कम हो गई है। बल्कि केंद्र का भवन भी दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। इसके पीछे वजह फंड की कमी है। 10 वर्ष पहले 525 रुपए से बढ़ाकर भरण पोषण की राशि प्रति बच्चा एक हजार रुपए की गई थी। लेकिन वर्ष 2013 के बाद से राशि नहीं बढ़ी। वर्तमान में 15 बच्चों के हिसाब से मात्र 15 हजार रुपए की राशि आती है। इसी में बच्चों का भरण-पोषण भी करना है और संस्था का खर्च भी निकालना है। दिन प्रतिदिन महंगाई के चलते केंद्र के संचालन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर राशि नहीं बढ़ाई गई तो केंद्र बंद होने की स्थिति में पहुंच सकता है।

### मप्र में एक मात्र संस्था जो 10 वीं तक गणित पढ़ाई जातीं हैं

ये मप्र की एकमात्र संस्था है, जहां पहली से 10वीं कक्षा तक दृष्टिहीन विद्यार्थियों को गणित पढ़ाया जाता है, जबकि अन्य संस्थाओं में दृष्टिहीन विद्यार्थियों को गणित के स्थान पर संगीत की शिक्षा दी जाती है। दृष्टिहीन ग्रामीण व आदिवासी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण (जैसे हैंडलूम), स्वरोजगार व पुनर्वसन के क्षेत्र में वास्तविक रूप से कार्य कर रही है, ताकि आदिवासी नेत्रहीन बालक-बालिका समाज में उचित व सम्मानजनक स्थान पा सके। यहां 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थी ब्रेल लिपि में अध्ययन करते हैं। जिन्हें पढ़ाने के लिए 2 प्रशिक्षक भी है। इसके अलावा ये बच्चे सामान्य बच्चों के साथ ही स्कूली शिक्षा लेते है। विद्यार्थी सांस्कृतिक गतिविधियों और खेलकूद में भी भाग लेते हैं। संस्था से शिक्षण व प्रशिक्षण प्राप्त कई छात्र आज मंत्रालय, कलेक्टरेट, बैंक व रेलवे में नौकरी कर सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

### वर्ष 2019 के पहले 35 बच्चे थे

केंद्र के प्रशिक्षक व प्रभारी वार्डन अभिनव दांडेकर कहते हैं वर्ष 2019 के पहले इस केंद्र में 35 दृष्टिहीन बच्चे थे। इसके बाद वर्ष 2019-20 में 25 बच्चे रह गए। फिर कोविड काल शुरू हो गया। इसके बाद 18 बच्चे थे। जबकि वर्तमान में सिर्फ 15 दृष्टिहीन बच्चे अध्ययनरत है। पहले खरगोन, बड़वानी के दृष्टिहीन बच्चे भी यहां पढ़ते थे। लेकिन वर्तमान में सिर्फ झाबुआ और आलीराजपुर जिले के बच्चे ही है।

## झाबुआ-अलीराजपुर जिले में आदिवासी समाज के इतिहास को लेकर बनेगी फ़िल्म

माही की गूंज, अलीराजपुर। फिरोज पठान

अलीराजपुर-झाबुआ जिले में आदिवासियों के समाज को लेकर फिल्म का निर्माण होने जा रहा है। जिसकी शूटिंग झाबुआ व अलीराजपुर जिले के अलावा मध्यप्रदेश के अन्य जिलों मे भी होगी।जिसमे फिल्म के निर्माता रमेश बघेल भील सेना के अध्यक्ष, निर्देशक संजीव चौहान, एसोसिएट प्रोड्यूसर अशरफ बैग मुंबई से पधार चुके हैं फिल्म की कहानी के राइटर सोहन डामोर (झाबुआ) के होकर ये फिल्म आदिवासियों की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर आधारित है। इस फिल्म का उद्देश आदिवासी समाज कल्याण एवं शिक्षा है। इस फिल्म में आदिवासियों की उत्पत्ति कैसे हुई और आदिवासियों का इतिहास और संघर्ष की कहानी पर आधारित होगी। फिल्म में मुंबई व मध्यप्रदेश के कलाकार सम्मिलित रूप से काम करेंगे। जिससे मध्यप्रदेश के कलाकार को भी रोजगार मिलेगा। फिल्म ऑल इंडिया लेवल की होकर बड़े बजट की होगी फिल्म का बजट 30 करोड़ रूपए निर्धारित किया गया है। वहीं फिल्म की कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित होगी। जिसमे आदिवासियों का देश की एकता एवं अखंडता में जो योगदान दिया है उसके बारे में बताया जाएगा।

## हम क्षेत्र के विकास के दृढ़ संकल्पित है- श्रीमति चौहान

माही की गूंज, नानपुर।

भारतीय जनता पार्टी की रतलाम- झाबुआ संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी व अलीराजपुर जिला पंचायत जिला अध्यक्ष श्रीमती अनिता चौहान ने क्षेत्र मे लाखों रुपये के निर्माण कार्यो के भूमिपूजन किया। ग्राम नानपुर मे कन्या माध्यमिक विधालय के प्रांगण मे पेवं ब्लॉक के लिए भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर श्रीमती चौहान ने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के समुचित विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। मेरे पति व भाजपा विधायक द्वारा जो वादे विधानसभा के समय किये थे उनमे से अधिकांश कार्यो की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके है। आपके आशीर्वाद से जनता ने नागर सिंह को चौथी बार विधायक बनाया है, अब वे मप्र शासन मे मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी ने अब इस संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है आपका आशीर्वाद चौहान परिवार पर पुन चाहिए।भाजपा की करनी व कथनी मे कोई अंतर नही है। आजादी के बाद इस क्षेत्र का पहली बार महिला को उम्मीदवार बनाया है। पूरे संसदीय क्षेत्र मे भाजपा विकास के कार्य प्रथमिकता से कर विकास का नया आयाम स्थापित किये जायेंगे।

इस अवसर पर उनके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश नागर, कैलाश चंद्र वाणी, स्थानीय सरपंच सकरी मौर्य, पूर्व सरपंच समरथ मौर्य, पूर्व उपसरपंच जितेन्द्र प्रसाद वाणी, मेहताब कनेश, मेहबूब पठान, देवेंद्र सोनी, महामंत्री डीम्पू राठौड़, सज्जन मौर्य, देवेंद्र वाणी, लाला बोहरा, रमेश मेंबर, गुलाब, सुखराम सहित विद्यालय के शिक्षक व आमजन उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत मे प्रधान पाठक ने आभार व्यक्त किया।

## रमजान का चांद नजर आने के बाद मुस्लिम समाज ने पाबंदी से शुरू की इबादत और रोजे

माही की गूंज, उदयगढ़। खलील मंसूरी

आसमान पर चांद दिखने के साथ ही रहमतों के महीने रमजान की शुरूआत हो गई और मंगलवार को पहला रोजा रखा गया। इबादत और बरकतों के इस महीने को लेकर बाजार में भी चहल-पहल दिखाई दी। गौरतलब है कि, माहे रमजान को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने पंद्रह दिनों पूर्व से ही तैयारियां करना शुरू कर दिया था और इसीके चलते घरों की सफाई के साथ ही मस्जिदों में भी विशेष रंग-रोगन और सजावट का काम शुरू हो गया था। सोमवार को चांद दिखने की तस्दीक होने पर मस्जिदों में तरावीह की विशेष नमाज अदा की गई। इस्लामी मान्यता के अनुसार माहे रमजान को अन्य महीनों से ज्यादा अजमत और बरकत वाला माना गया है।

कहा जाता है कि, इस माह में की गई खुदा की इबादत बाकि महीनों से अफजल होती है। यही कारण है कि, रमजान के पहले दिन से ही मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ बढने लगी है और हर कोई अपने रब को मनाने के लिए सजदे में सिर झुकाता नजर आ रहा है।

### तरावीह की विशेष नमाज शुरू

उल्लेखनीय है कि, सोमवार को माहे मुबारक रमजान की शुरूआत के साथ ही मस्जिदों में 20 रकआत के साथ पढ़ी जाने वाली तरावीह की विशेष नमाज का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ईशा की नमाज के समय पढ़ी जाने वाली इस नमाज की बड़ी फजीलत है। चांद दिखने के बाद मुस्लिमजनों ने अपने रब की रजा के लिए सेहरी करते हुए मंगलवार को पहला रोजा रखा और रोजे रखने का यह सिलसिला तीस दिनों तक जारी रहेगा।

उदयगढ़ मोहम्दीया कमेटी सदर कयूम खान पठान और नायब सदर द्वारा हमें जानकारी देते हुए बताया गया कि, उदयगढ़ के साथ-साथ पूरे देश के मुसलमान पूरे महीने रोजा और नमाज पूरी पाबंदी के साथ अदा करेंगे। साथ ही सोमवार को चांद दिखने के बाद तरावीह की नमाज अदा की गई।

## महाकाल की भक्ति में डूबे गोविंदा

माही की गूंज, उज्जैन।

बॉलीवुड सितारे भगवान की पूजा करने के लिए देश के अलग-अलग मंदिरों में पहुंचते हैं। इसी दौरान गोविंदा को भी बाबा महाकाल के दर्शन करते हुए देखा गया। वो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-पाठ करते हुए देखे गए। सामने आए वीडियो में वो मंदिर में नजर आ रहे हैं। बता दें कि, इससे पहले भी कई सितारों को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पूजा-अर्चना करते हुए स्पॉट किया जा चुका है।

### महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे गोविंदा

सामने आए वीडियो में वो भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर गोविंदा मगन हो कर पूजा करते दिख रहे हैं। वहीं, इस दौरान मंदिर में मौजूद पंडीत और अन्य सदस्य उन्हें एक-एक कर ढेर सारी फूलों की माला पहनाते नजर आ रहे हैं। उन्हें भगवान के आर्शिवाद के रूप में एक फूल भी दिया गया, जिसे देख गोविंदा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।

### नंदी के कान में मांगी मनोकामना

गोविंदा भगवान के दर्शन के बाद नंदी महाराज के दर्शन के लिए भी पहुंचे. इस दौरान वो कान में मनोकामना मांगते नजर आ रहे हैं। वीडियो में मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे रहा है। वहीं, ढेर सारे लोग भी परिसर में खड़े दिख रहे हैं।

### पहले वाइफ और बेटे के साथ पहुंचे थे अभिनेता

गोविंदा पूजा-पाठ के लिए हमेशा आगे रहते हैं. वो पहली महाकालेश्वर मंदिर नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले भी वो उज्जैन पहुंचे थे। उस वक्त गोविंदा के साथ उनकी वाइफ और बेटा भी दिखाई दिया है। जबकि अब

वो अकेले नजर आए। बता दें कि, गोविंदा का यह वीडियो इंटरनेट पर छा गया है। फैंस को उनका भक्ति वाला अंदाज पसंद आ रहा है।

# भोजशाला फिर चर्चा में, जानिए क्या है विवाद और क्यों कहा जाता है इसे दूसरी अयोध्या

माही की गूंज, धार। विक्रम सिंह राठौर

जिले के विवादित सरस्वती मंदिर भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ का बड़ा आदेश आया है। कोर्ट ने यहां एएसआई के सर्वे को अनुमति दे दी है। बता दें कि, भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर माना जाता है तो मुस्लिम इसे मस्जिद बताते हैं। इसका विवाद भी लंबे समय से चला आ रहा है।

### क्यों संवेदनशील है भोजशाला

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला लंबे समय से विवाद में रही है। करीब 800 वर्ष पुरानी इस भोजशाला को लेकर हिंदू-मुस्लिम मतभेद हैं। हिंदुओं के अनुसार भोजशाला यानी सरस्वती का मंदिर है। जबकि मुस्लिम इसे पुरानी इबादतगाह बताते हैं। हिंदू संगठन के लोग बताते हैं कि, धार की ऐतिहासिक भोजशाला उसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह राजा भोज द्वारा स्थापित सरस्वती सदन है यहां कभी 1000 वर्ष पूर्व शिक्षा का एक बड़ा संस्थान हुआ करता था। बाद में यहां पर राजवंश काल में मुस्लिम समाज को नमाज के लिए अनुमति दी गई, क्योंकि यह इमारत अनुपयोगी पड़ी थी। पास में सूफी संत कमाल मौलाना की दरगाह है। ऐसे में लंबे समय से मुस्लिम समाज में नमाज अदा करने का कार्य करते रहे। परिणाम स्वरूप पर दावा करते हैं कि यह भोजशाला नहीं बल्कि कमाल मौलाना की दरगाह है।

जबकि हिंदू समाज यह दावा करता है कि, यह दरगाह नहीं बल्कि राजा भोज के काल में स्थापित सरस्वती सदन भोजशाला है। इतिहास में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि यहां से अंग्रेज मां सरस्वती की प्रतिमा निकाल कर ले गए जो कि वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित भी है। विवाद की शुरुआत 1902 से बताई जाती है, जब धार के शिक्षा अधीक्षक काशीराम लेले ने मस्जिद के फर्श पर संस्कृत के श्लोक खुदे देखे थे और इसे भोजशाला बताया था। विवाद का दूसरा पड़ाव 1935 में आया, जब धार महाराज ने इमारत के बाहर तख्ती टंगवाई जिस पर भोजशाला और मस्जिद कमाल मौलाना लिखा था। आजादी के बाद ये मुद्दा सियासी गलियारों से भी गुजरा। मंदिर में जाने को लेकर हिंदुओं ने आंदोलन किया। जब-जब वसंत पंचमी और शुक्रवार साथ होते हैं, तब-तब तनाव बढ़ता है। विवादों के चलते ही इसे इलाके की अयोध्या भी कहा जाता है।

### 1456 में भोजशाला को ढहाया गया

इतिहासकारों के अनुसार 13वीं और 14वीं सदी में मुगलों ने देश में आक्रमण किया। 1456 में महमूद खिलजी ने भोजशाला में मौलाना कमालुद्दीन के मकबरे और दरगाह का निर्माण कराया। साथ ही प्राचीन सरस्वती मंदिर भोजशाला को ढहाकर उसके अवशेषों से उसके भोजशाला का रूप परिवर्तित कर दिया। आज भी प्राचीन हिंदू सनातनी अवशेष भोजशाला में स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। इसके बाद से ही भोजशाला मुक्ति को लेकर विवाद जारी है।

### राजा आनंद राव पवार की तबीयत बिगड़ी तो मिली नमाज की अनुमति

अंग्रेजों के शासनकाल में हुए सर्वे में यहां हुई खुदाई में भोजशाला में पूर्व में स्थापित माता सरस्वती वाग्देवी की प्रतिमा मिली, जिसे बाद वे अपने साथ ले गए। सदियों तक वीरान पड़ी रही भोजशाला और विवाद के बीच रियासत काल में यहां राज परिवार के घोड़ों के लिए घास और चारा भरा जाता था। इसी बीच तत्कालीन धार के राजा आनंद राव पवार चतुर्थ की तबीयत बिगड़ी, उनकी तबीयत में सुधार नहीं होने पर मुस्लिम समाज ने दुआ करने की बात कहकर भोजशाला में जगह मांगी। तत्कालीन दीवान खंडेराव नाटकर ने 1933 में मुस्लिम समाज को भोजशाला में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी थी। वहीं, हिंदू समाज प्रतिवर्ष बसंत पंचमी पर यहां आयोजन करता रहा।

### तत्कालीन दिग्विजय सरकार ने जारी किया एक तरफा आदेश

देश की आजादी के बाद भोजशाला का विवाद और बढ़ते हुए कानूनी लड़ाई में बदल गया। इस बीच 1995 में हुई घटना से बात बिगड़ गई। जिसके बाद प्रशासन ने मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। 1997 में प्रशासन ने भोजशाला में आम नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरान हिंदुओं को वर्ष में एक बार बसंत पंचमी और मुसलमान को प्रति शुक्रवार एक से तीन बजे तक नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई।

6 फरवरी 1998 को पुरातत्व विभाग ने भोजशाला में आगामी आदेश तक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन मुस्लिम मुसलमानों को नमाज की अनुमति जारी रही। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार में आए इस एक तरफा आदेश से विवाद और गहराया। हालांकि, कोर्ट के जरिए हिंदुओं को 2003 में फिर से पूजा करने की अनुमति मिल गई और पर्यटकों के लिए सशुल्क भोजशाला को भी खोल दिया गया। इसके बाद से लगातार भोजशाला को लेकर न्यायालयीन लड़ाई जारी है। हर साल बसंत पंचमी पर हिंदू समाज यहां कार्यक्रम करता है। लेकिन, शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ने से कई बार विवाद की स्थिति बनती है। ऐसे में कई पूरा धार जिला तनाव में रहा है।

### चुनाव में भी मुद्दा बनी भोजशाला

2003 के विधानसभा चुनाव में धार की भोजशाला को भी मुद्दा बनाया। भाजपा ने इस समय प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की और उमा भारती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थीं। इसके बाद से भाजपा सरकार लंदन के एक म्यूजियम में रखी मां सरस्वती वाग्देवी की प्रतिमा को लाकर भोजशाला में स्थापित कर इसे मुक्ति कराने की बात कही थी। अब न्यायालय में भोजशाला के सर्वे के फैसले को सुरक्षित रखे जाने के बाद एक बार फिर इसकी चर्चा शुरू हो गई।

### क्या है 1902 की रिपोर्ट में

हाईकोर्ट में आर्कियोलॉजिक्ल सर्वे आफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन धार, मांडू के दौरे पर आए थे। उन्होंने भोजशाला के रखरखाव के लिए 50 हजार रुपए खर्च करने की मंजूरी दी थी। तब सर्वे भी किया गया था। 1951 को धार भोजशाला को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तब हुए नोटिफिकेशन में भोजशाला और कमाल मौला की मस्जिद का उल्लेख है। याचिका हिंदू फॉर जस्टिस ट्रस्ट की तरफ से लगाई गई थी। इसके अलावा छह अन्य याचिकाएं भी इस मामले में पूर्व में लगी हैं। ट्रस्ट की तरफ से अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने पक्ष रखते हुए बताया था कि 1902 में हुए सर्वे में भोजशाला में हिंदू चिन्ह, संस्कृत के शब्द आदि पाए गए हैं। इसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच होना चाहिए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो।

# झाबुआ जिला नए आईएएस अधिकारियों की पाठशाला...?

## नवैलों की जगह अनुभवी कलेक्टर जिले को क्यों नही देना चाहती सरकार...?

**माही की गूंज, संजय भटेवरा।**

**झाबुआ। वैसे तो यह जिला हमेशा से ही पिछड़ा हुआ रहा है और इस पिछड़े पन को दूर करने के लिए कई सरकारों ने कई तरह की योजनाएं बनाकर इस जिले के साथ स्वांग किया है। मगर कोई भी सरकार इस जिले को अब तक भी पिछड़े पन से उभारने में कामयाब क्यों नहीं हो सकी है। यह एक बड़ा सवाल है...? कहने को तो पिछड़ा जिला होने के कारण यहां सरकार द्वारा तमाम तरह की कवायदें की जाती रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह कवायदें अब तक ढाक के तीन पात ही साबित हुई है और जिला अब भी पिछड़ा का पिछड़ा ही पड़ा है। इसका एक सबसे बड़ा कारण जो सामने दिखाई पड़ रहा है वह है इस जिले से कलेक्टरों के तबादले। जिले में बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि, कोई कलेक्टर जिले में अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर सका हो। इसके उलट स्थितियां इतनी गंभीर है कि, इस जिले में कोई भी कलेक्टर बहुत अधिक हुआ तो सालभर या उससे कुछ माह उपर-नीचे निकालता है और उसका तबादला कर दिया जाता है। पिछले डेढ़ साल में यह जिला कलेक्टरों की फहरिस्त में 4 कलेक्टर देख चुका है। इसमें से सबसे अधिक समय करीब 11 माह कलेक्टर तन्वी हुड्डा ने अपनी सेवाएं जिले को दी है। अब उनका भी तबादला हो चुका है और 2014 बैच की आईएएस अधिकारी नेहा मीना ने 49 वें कलेक्टर के रूप में जिले की कमान संभाली है। हालांकि नेहा मीना को पहली बार कलेक्टरी का मौका झाबुआ में ही मिल रहा है।**

अब सवाल यह कि क्या वाकई यह जिला अब आईएएस जैसे अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनकर रह गया है...? क्योंकि इस जिले में अब अनुभवी अधिकारियों का आना लगभग बंद हो चुका है। या यूं कहें कि सरकार ने अब इस जिले को सिर्फ नवादे आईएएस अधिकारियों की पाठशाला या ट्रेनिंग सेंटर भर समझ लिया है। जिले के विकास से सरकार को कोई लेना-देना दिखाई पड़ ही नही रहा है। क्योंकि विकास के लिए चाहिए अनुभवी और साधे हुए अधिकारी या कलेक्टर और सरकार वह इस जिले को देना ही नहीं चाहती। पिछले 18 माह में 4 कलेक्टरों की सूरत यह जिला देख चुका है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में किस तरह के विकास कार्यों को अंजाम दिया गया होगा। पिछले दो कलेक्टर जिले में फ्रेशर ही रहे है और वह भी महिला के रूप में और अब फिर से एक नई कलेक्टर वह भी पहली बार ही जिले में कलेक्टरी करने आई है।

जिले की 49 वीं कलेक्टर नेहा मीना।

### जिले से सरकार का सौतेला व्यवहार

आखिर ऐसा क्यूं है कि, इस जिले में सरकार किसी अनुभवी कलेक्टर को भेजने से कतराती नजर आ रही है। या फिर सरकार ने यह ठान लिया है कि, झाबुआ जिले और उसमें बसने वाले पिछड़े आदिवासी समाज को आगे आने ही नहीं दिया जाए। क्योंकि एक लंबे अर्से से जिले में कोई अनुभवी कलेक्टर नहीं भेजा गया है। लंबे समय से जिले में फ्रेशर आईएएस अधिकारियों की ही पोसिंटग की जा रही है। इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि, जिला अब नए आईएएस अधिकारियों के लिए पाठशाला या प्रयोगशाला बनकर रह गया है। नए अधिकारी जिले में भेजने का नुकसान यह होता है कि, या तो ये यहां के माहौल को समझ नहीं पाते या फिर कलेक्टरी का अति उत्साह और यहां की राजनीति उन्हे यहां टिकने नहीं देता। इन सारी ही स्थितियों में अगर नुकसान होता है तो वह सिर्फ और सिर्फ जिले की आम जनता का ही होता है। जिस तरह से जिले में सरकार द्वारा कलेक्टर बदले जा रहे है उससे तो यह अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि, इस जिले के विकास और यहां की जनता से सरकार को कितना सरोकार है। क्योंकि इस आदिवासी बाहुल जिले में अगर सरकार वाकई में विकास करना चाहती तो इस तरह से नए-नवादे आईएएस अधिकारियों को जिले में न भेजते हुए अनुभवी और सधे हुए अधिकारियों को जिले में पदस्थ करती और सही मायनों में जिले का विकास करती। मगर यहां स्थितियां बिल्कुल उलट है। और सरकार का जिले से इस तरह का व्यवहार सौतेला ही माना जाएगा।

### हर कलेक्टर अपने आपको सौभाग्यशाली क्यों मानता है...

जिले में वैसे तो 48 कलेक्टर आकर जा चुके है। इनमें कई कलेक्टर अच्छे और अनुभवी रहे है, लेकिन एक लंबे समय से जिले में कोई अनुभवी कलेक्टर नही आया है। पिछले तीन तो लगभग फ्रेशर ही है जिन्हे कलेक्टरी करने का मौका ही झाबुआ जिले में प्राप्त हुआ। मगर हर कलेक्टर जब भी जिले में पदस्थ होता अपने पहले वक्तव्य में यह बात जरूर कहता है कि ''यह हमारा सौभाग्य है कि हमें झाबुआ जिले जैसे आदिवासी बाहुल क्षेत्र में काम करने या सेवा देने का मौका मिला।'' हालांकि इस वाक्य को कुछ पिछले कलेक्टरों ने अपने अंदाज में सार्थक करते हुए जिले में खूब भ्रष्टाचार किया और शिकायतों के बाद वे अपने सौभाग्य के साथ जिले से रवाना भी हुए है। अब नेहा मीना यहां की कलेक्टर बनकर आई है और वे भी इस जिले से अपनी कलेक्टरी की शुरूआत कर रही है। उनके अपने वक्तव्य भी कुछ ऐसे ही है, वे भी इस जिले में कलेक्टर के रूप में अपनी पदस्थी को सौभाग्य मान रही है। मगर उनका यह सौभाग्य किस तरह का है यह तो समय के गर्त में है।

### पांचवीं महिला कलेक्टर

हालांकि महिला कलेक्टरों की फहरिस्त में नेहा मीना का नाम पांचवे नंबर पर आता है। इसके पहले चार महिला कलेक्टरों ने जिले की कमान संभाली मगर इनमें सबसे सफल जिले की पहली महिला कलेक्टर श्रीमती जयश्री कियावत ही रही है। इनके बाद श्रीमती अरूणा गुप्ता, रजनी सिंह, तन्वी हुड्डा कुछ खास नहीं कर पाई। अब यह भी देखने योग्य होगा कि नेहा मीना पांचवी महिला कलेक्टर के रूप में यहां कैसा काम कर पाती है। हालांकि यह उनका पहला अनुभव कलेक्टर के रूप में होगा, लेकिन कोशिशें तो की ही जा सकती है। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिले को आने वाले नए कलेक्टरों से वैसे भी कोई उम्मीद तो नहीं रहती क्योंकि अब इस जिले में कलेक्टरों का आना-जाना एक आम बात हो गई है। क्योंकि उम्मीदों पर खरा तो वही उतर सकता है जो जिले में टिक सके, वरना आने-जाने वालों से उम्मीदें करना तो बैमानी है।

खैर जो भी हो वह तो समय के गर्त में है पर माही की गूंज परिवार आपका जिले में हार्दिक स्वागत करता है और जिले की आम जनता की ओर से उम्मीद करते है कि, इस पिछड़े जिले की आम जनता के हितों के लिए आप कुछ अच्छा ही करेंगे।

# प्रशासनिक अधिकारी को अपने पैरों की जूती समझने वाला देवेंद्र अब न्यायालयीन व्यवस्था को भी अपने अधीन मानने लगा

**माही की गूंज, झाबुआ।**

**औद्योगिक क्षेत्र में बर्फ फैक्ट्री चलाने वाला देवेंद्र भानपुरिया की बदनियति के साथ की जाने वाली कारस्तानियां एक के बाद एक सामने आती ही जा रही है। लेकिन इसके पीछे क्या उद्देश्य है यह वह स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। यह भी है की बात अगर नियति संगत हो तो वह अपने उद्देश्य को भी स्पष्ट कर पाए। लेकिन देवेंद्र भानपुरिया की कहानी उसकी बदनियति के साथ ही शुरू होती है और बदनियति के साथ ही खत्म होती है।**

देवेंद्र नाम की यह एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में सामने आता है कि, यह अपना हित साधने व अपने आप को प्रभावशील साबित करने के लिए अपनी बदनियति के साथ किसी के ऊपर भी किसी प्रकार के भी बदनुमा दाग लगाने में संकोच नहीं करता है। जिसे समाज में वर्तमान ही नहीं वरन् पूर्व में बदनियति के साथ किए गए कारनामे भी सामने आने लग गए हैं। देवेंद्र के बारे में कहा जाता है कि, यह इतना गिरा हुआ इंसान है कि अपने ही परिवार में झुठे व अनर्गल ऐसे बदनुमा दाग लगाने में कभी संकोच नहीं किया जिसके बाद व्यक्ति आत्महत्या तक कर ले। पूर्व में अपने ही भाई परिवार में ऐसे गंदे व बे-बुनियाद आरोप लगा चुका है कि, देवेन्द्र के ससुर जो की कलाल समाज के गौरव रहे हैं और समाज के सम्माननीय रहे शंभूलाल जी बसेर सारंगी को उनके अनगर्ल आरोपो रूपी कृत के चलते देवेंद्र के पिता एवं पंचों के समक्ष समाज के गौरव श्री शंभूलाल जी ने अपनी आन- बान- शान रूपी सर की पगड़ी तक चरणों में रख बदनुमा आरोपो का पताक्षेत्र किया था। लेकिन देवेंद्र इतने बड़े वाक्ये के बाद भी नसियत लेकर कभी सही रास्ता नहीं चुना और आज भी बदनियति के साथ तथा अपने आप को प्रभावशील साबित करने के लिए फिर से पूर्व की तरह झूठे आरोपों के साथ समाज की मर्यादा को खंडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

वही अपनी निजी द्वेषता निकालने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों पर कहीं आरोप लगाता है तो कहीं उन्हें अपने पैरों की जूती भी मानता है। इतना ही नहीं देवेंद्र अब तो न्यायालयीन व्यवस्था को भी अपनी बदनियति के साथ लोगों को ब्लैकमेल करने हेतु अपने अधीन मानने लगा है।

वर्तमान में देवेंद्र भानपुरिया की कहानी सोशल मीडिया से शुरू हुई जिसमें सामाजिक चर्चाओं से भटक कर देवेंद्र, समाज के वृद्ध पूर्व सचिव एजेनलाल भानपुरिया जो कि रिटायर्ड शिक्षक है से लेकर समाज के सभी सदस्यों को मूर्ख, बेईमान व अनपढ़ मानने लगा और स्वयं को समाज का पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी व बाहुबली मानने लगा। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर सीधे रूप से अपनी बर्फ फैक्ट्री में मांसाहारी ढाबे का संचालन व अवैध शराब बेचने का स्वीकार किया। तथा जिले के एसपी तक को अपने पैरों की जूती मानते हुए कहा कि, किसी ने मां का दूध पिया हो तो एसपी को फोन लगाकर शराब पकड़वा दे तो मैं जानू। इतना ही नहीं देवेंद्र ने सोशल मीडिया पर स्वयं ने यह भी पुष्टि की कि वो महीने के बर्फ फैक्ट्री में मय जीएसटी के 2 से 3 लाख रुपए महीना कमा सकता है।


देवेंद्र नही आ रहा अपनी बदनुमा कारस्तानियो से बाज।

उक्त देवेंद्र द्वारा स्वीकार की गई बात जब माही की गूंज में आवाज बनकर उठी तो सर्वप्रथम मजबूरीवश देवेंद्र भानपुरिया को फैक्ट्री में बिना परमिशन के संचालित मांसाहारी ढाबा व अवैध शराब के व्यवसाय को बंद करना पड़ा। बस फिर क्या था, उसके बाद तो देवेंद्र भानपुरिया ने अपने सारे होश-हवास को ताक में रख दिया और अपनी बौखलाहट के साथ वो सब कुछ करने लगा जिसमें सामाजिक सम्मान व प्रतिष्ठा भी खंड-खंड हो जाए। नतीजन किसी समाज के घर जीएसटी टीम को भेजने की बात कहकर धमकाने लगा और दूसरी और उन्हें सचेत रहने की हिदायत भी देने लगा। वही अपने ही भाई को मैसेज व जन्म देने वाली मां को फोन लगाकर कहता है आपके घर एक-दो दिन में आबकारी व पुलिस की दबिश गिरने वाली है देख लेना कहकर धमकाने में पीछे नहीं रहा। जब समाज में इस बौखलाए हुए देवेंद्र को जवाब देना ही समाज के लोगों ने छोड़ दिया तो वह पूर्व की तरह फिर से ऐसी नीचपन पर उतर आया कि, जिसमें परिवार पर ही लगाए गए झूठे आरोपो में समाज के सम्मानीय एवं दिवंगत ससुर श्री शंभूलाल जी बसेर ने अपनी शान व सर का ताज रूपी पगड़ी को पंचों के कदमों में इनकी गलतियों को पटाछेप करने के लिए रखनी पड़ी थी।

इसी तरह पुनः गलती दोहराते हुए माही की गूंज के प्रधान संपादक एवं समाज में सम्मान की दृष्टि से देखे जाने वाले संजय भटेवरा पर एक समाज की महिला एवं एक अन्य महिला के साथ अवेध संबंध होने के आरोप तक लगा डालें। मामले में पुलिस में शिकायत के साथ समाज मे भी सामाजिक समाधान हेतु आवेदन दिया।

वहीं देवेंद्र की सासूमां देवलोक गमन हुए जिनकी अंत्येष्टि भी ठंडी नहीं हुई थी कि, सोशल मीडिया पर कई तरह की अनगर्ल बातों के साथ मेघनगर एम 3 व पेटलावद के एम 4 होटल के संचालक जीवनलाल पडियार व पत्रकार संजय भटेवरा पर देह व्यापार तक चलाने का बदनुमा आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं देवेंद्र ने सोशल मीडिया में लिखे लेख में कह रहा है कि, जीवन पडियार व संजय भटेवर के मोबाइल कॉल डिटेल व व्हाट्सएप चैट की डिटेल निकाली जाए तो कहां से किसे बुलाते हैं और कहां-कहां से व्यापार का कार्य करने वाली पहुंचती है और कहां-कहां व्यापार हेतु भेजा जाता है जिसकी संपूर्ण जानकारी निकालकर आ सकती है। के आरोप के साथ स्थानीय पुलिस व प्रशासन पर भी इनडायरेक्टली आरोप लगाए गए हैं। तय है किसी प्रकार का भी अवैध व्यापार चलाने में प्रशासनिक साठ-गाँठ जरूरी होती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि देवेंद्र भानपुरिया द्वारा लगाए गए आरोप, कॉल डिटेल के साथ पुष्टी करें और देवेंद्र भानपुरिया के लगाए आरोप असत्य पाए जाने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई करें।

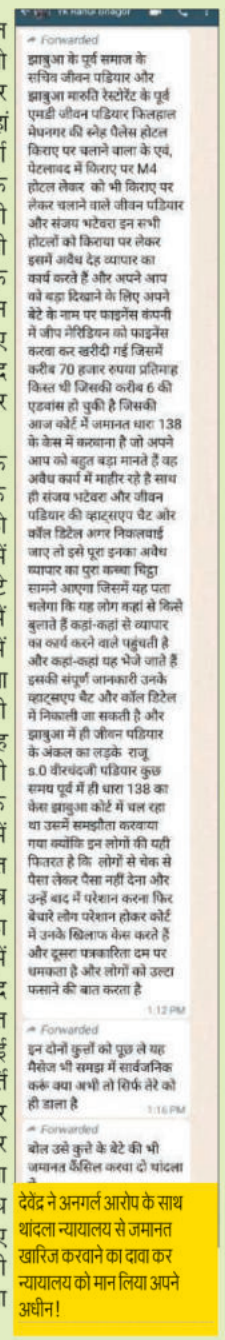

देवेंद्र भानपुरिया अपनी गिरी हुई हरकत के साथ यही तक नहीं रुका, एक 138 के न्यायालयीन मामले में समाज के कुछ लोगों को पर्सनल मैसेज डालकर यह भी कह रहा है जिसमें जीवनलाल पडियार को कुत्ता बताकर उसके बेटे की जमानत थांदला से उसकी जमानत मैं कैंसिल करवा दू तथा सामाजिक ग्रुप में ब्लैकमेल वाले मेसेजो को वायरल कर दू क्या की धमकी भी खुल्ले रूप से दी गई। किसी की जमानत लेना या जमानत खारिज करना यह न्यायालय का अधिकार है और हमारी न्यायालयलीन व्यवस्था को हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चेलेंज नहीं कर सकते है। ऐसे में देवेंद्र भानपुरिया थांदला न्यायालय से जमानत कैंसिल करवा देने की बात किस अधिकार व प्रभाव के साथ कर रहा है यह एक बड़ा जांच का विषय है। ऐसे में जीवनलाल पडियार पुलिस में मामले को ले जाते हैं, तो पुलिस को भी देवेंद्र भानपुरिया द्वारा लिखी गई बात की पुष्टि कर सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति अपने निजी द्वेषभाव या निजी स्वार्थपुर्ति के साथ किसी भी अन्य व्यक्ति व प्रतिष्ठान पर बेबुनियाद व बदनुमा आरोप ना लगा सके और ना ही कोई अपने आप को न्यायालयीन व्यवस्था से ऊपर मानकर न्यायालयलीन व्यवस्था में सेंध लगाने की कोई बात नही कर सके। इसलिए पुलिस को देवेंद्र द्वारा सोशल मीडिया पर लिखी गई बात व आरोप की जांच अवश्य करना चाहिए।



देवेंद्र ने अनगर्ल आरोप के साथ थांदला न्यायालय से जमानत खारिज करवाने का दावा कर न्यायालय को मान लिया अपने अधीन!

# विकास कार्यों के ठीकानें नहीं, जनप्रतिनिधियों में हो रही जूतम पैजार

**माही की गूंज, झाबुआ।**

मंगलवार को नगरपालिका में शहर के विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर आम सहमति से पारित करने के लिए परिषद का सम्मेलन आयोजित किया गया था। विकास कार्यों के लिए किए जा रहे इस सम्मेलन में गहमा-गहमी हो गई और यह सम्मेलन हंगामें की भेंट चढ़ गया। वैसे नगरपालिका में बैठी परिषद को यह दूसरा वर्ष चल रहा है लेकिन शहर के विकास कार्यों के नाम पर कुछ खास अब तक देखने को नहीं मिल पाया है। उसके उलट स्थिति यह हो चली है कि, अब विकास कार्यों के ठिकानें नहीं है और जनप्रतिनिधियों में जमकर जूतम पैजार हो रही है। पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से फंड की कमी का रोना रोने वाली नगरपालिका परिषद में अब पाषर्दों व जनप्रतिनिधियों की हालत ऐसी हो चली है कि खीर आई है तो सबमें बंटनी चाहिए नहीं तो न खाएंगे और ना खाने देंगे।

नगरपालिका के सभागृह में मंगलवार को परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। सम्मेलन में वार्ड 8 के पार्षद विजय चौहान और उपाध्यक्ष लाखनसिह सौलंकी एक प्रस्ताव पर आमने-सामने हो गए। दोनों के बीच जमकर बहस हुई। यह बहस उपाध्यक्ष के वार्ड में नाली निर्माण के प्रस्ताव को लेकर हुई। जबकि वार्ड 8 के पार्षद विजय चौहान का कहना था कि, क्या झाबुआ में एक ही वार्ड है, विकास कार्य हो रहे है तो सभी वार्डों में काम होना चाहिए। चूंकि वार्ड 9 उपाध्यक्ष लाखनसिंह सौलंकी का है तो उन्होने पार्षद के जवाब में तत्काल विरोध दर्ज करवाते हुए पूरी दादागिरी के साथ बोले - किसको आपत्ती है। जिस पर पार्षद विजय चौहान ने कहा कि, आपत्ती किसी को नही है बस हम चाहते है कि, सभी वार्ड में काम होना चाहिए। बस यहीं से बात ने तूल पकड़ लिया और इसके बाद दोनों में जमकर बहसबाजी होने लगी। पार्षद और उपाध्यक्ष दोनों जोर-जोर से चिल्लाकर व टेबल ठोक-ठोक कर बहस करने लगे। हंगामा इतना जोर से हो रहा था कि इसकी आवाजें नगरपालिका परिसर की हदों को पार कर बाहर जा रही थी। वैसे तो नगरपालिका के आयोजित इस सम्मेलन में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई, मगर महज एक नाली के मुद्दे ने इस पूरे सम्मेलन को हंगामें में तब्दील कर दिया।

उधर बैठक में वार्ड क्रंमाक 10 के पार्षद महेंद्र तिवारी का कहना था कि, परिषद का एजेंडा पार्षदों से बनवाने की बजाय उन पर थोप दिया जाता है। इसके अलावा उन्होनें अब तक हुए सम्मेलन की प्रोसिडिंग की पूरी जानकारी भी सभी पार्षदों को देने की बात कही। सम्मेलन में उपस्थित मीडिया कर्मियों से अधिकारियों ने बाहर जाने को कहा। उनका कहना था कि, बाहरी व्यक्ति सम्मेलन में नहीं रह सकते। जब मीडियाकर्मी ने वहां बैठे अन्य लोगों पर सवाल उठाए तो अधिकारियों ने उन्हे भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी बात को लेकर एक पार्षद पति ने मीडियाकर्मी से दुर्व्यवहार करते हुए धक्का - मुक्की भी की। मीडियाकर्मी ने इस संबंध में थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कुल मिलाकर बात यह है कि, पिछले वर्ष से गद्दी पर बैठी कंगली परिषद में विकास कार्यों के ठिकानें नहीं और जनप्रतिनिधियों में जमकर जूतम-पैजार हो रही है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422